DD

RNI No. DLHIN/25/A2321

दिव्य दिल्ली

दिल्ली से प्रकाशित दैनिक समाचार पत्र

वर्ष: 01, अंक: 05, पृष्ठ: 08 infodivyadelhi@gmail.com

शुक्रवार, 12 सितम्बर, 2025 तदनुसार 19 भाद्रपद विक्रमी सम्वत 2082 | www.divyadelhi.com | facebook.com/divyadelhi तापमान अधिकतम 30 डिग्री न्यूनतम 25 डिग्री | सूयोदय 05.25 | सूर्यास्त 06.50

भारत-मॉरीशस पार्टनर नहीं, परिवार: पीएम मोदी

मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने काशी में भव्य स्वागत के लिए पीएम को धन्यवाद किया

राजेश चौहान
वाराणसी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वाराणसी में मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम को चागोस समझौता संपन्न होने पर बधाई दी। वहीं मॉरीशस के प्रधानमंत्री ने काशी में भव्य स्वागत के लिए पीएम को धन्यवाद किया।

काशी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह मेरे लिए गर्व की बात है कि मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में आपका स्वागत करने का अवसर मिल रहा है। प्राचीन काल से काशी भारत की सभ्यता और सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक रही है। हमारी संस्कृति और संस्कार सदियों पहले भारत से मॉरीशस पहुंचे और वहां की जीवन-पद्धति में रच-बस गए। काशी में मां गंगा की अविरल धारा की तरह, भारतीय संस्कृति का अविरल प्रवाह मॉरीशस को समृद्ध करता रहा है और आज, जब हम मॉरीशस के साथियों का काशी में स्वागत कर रहे हैं, तो यह सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मिलन है इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि भारत और मॉरीशस सिर्फ पार्टनर नहीं बल्कि एक परिवार है...।

भारत हमेशा मॉरीशस संप्रभुता के साथ से खड़ा

भारत हमेशा मॉरीशस के उपनिवेशवाद-विरोधी रुख और उसकी संप्रभुता के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत ने मॉरीशस की प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विशेष आर्थिक पैकेज तैयार किया है, जिससे बुनियादी ढांचे को मजबूती, रोजगार सृजन और स्वास्थ्य सेवाओं को नई ऊर्जा मिलेगी। मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष मॉरीशस में यूपीआई और रूपे कार्ड की शुरूआत हुई थी। अब दोनों देश स्थानीय करंसी में व्यापार की दिशा में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने हिंद महासागर क्षेत्र को दोनों देशों की साझा प्राथमिकता बताते हुए कहा कि भारत मॉरीशस के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र की सुरक्षा और उसकी समुद्री क्षमता को मजबूत करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। भारत ने हमेशा इस क्षेत्र में प्रथम प्रत्युत्तरदाता और शुद्ध सुरक्षा प्रदाता के रूप में भूमिका निभाई है।

मॉरीशस के पीएम को चागोस समझौता संपन्न होने पर बधाई देता हूं:

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज हमने द्विपक्षीय सहयोग की सभी पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार साझा किए। मैं मॉरीशस के प्रधानमंत्री नवीनचंद्र रामगुलाम को चागोस समझौता संपन्न होने पर बधाई देता हूं।

द्विपक्षीय वार्ता के बाद बोले पीएम मोदी, मॉरीशस की संप्रभुता की ऐतिहासिक जीत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये मॉरीशस की संप्रभुता की एक ऐतिहासिक जीत है। भारत ने हमेशा उपनिवेशवाद और मॉरीशस की संप्रभुता की पूर्ण मान्यता का समर्थन किया है और इसमें भारत, मॉरीशस के साथ दृढ़ता से साथ खड़ा रहा है।

मॉरीशस के विकास में साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मॉरीशस के विकास में एक विश्वसनीय और प्राथमिक साझेदार होना भारत के लिए गर्व की बात है। आज हमने मॉरिशस की आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए एक विशेष आर्थिक पैकेज पर निर्णय लिया है।

भारत वापस लाया आएगा भगोड़ा कारोबारी चोकसी

नई दिल्ली

पंजाब नेशनल बैंक के 13,000 करोड़ रुपये के धोखाधड़ी मामले में वांछित भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के खिलाफ प्रत्यर्पण की कार्यवाही सोमवार को बेल्जियम की एक अदालत में शुरू होने की संभावना है। अदालती सुनवाई बेल्जियम के संघीय अभियोजकों द्वारा सीबीआइ और भारत के विदेश मंत्रालय के सहयोग से की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि चोकसी 2023 से बेल्जियम में रह रहा है। वह इलाज के लिए एंटीगुआ और बारबुडा से इस यूरोपीय देश में स्थानांतरित हुआ था। सीबीआइ को जनवरी 2024 में बेल्जियम में उसकी मौजूदगी की सूचना मिली थी, जिसके बाद उस यूरोपीय देश को प्रत्यर्पण अनुरोध भेजा गया था।

'भारत आज की महाशक्तियों जैसा नहीं बनेगा',

भारत का चरित्र सेवा या निस्वार्थ सेवा में निहित है: मोहन भागवत

भागवत ने कहा कि भारत दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा

नागपुर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत ने बुधवार को कहा कि भारत का चरित्र सेवा या निस्वार्थ सेवा में निहित है। भारत की यही भावना आज की महाशक्तियों की तरह बनने के बजाय तटस्थता से विश्व की सेवा करने में विश्वास रखता है। उन्होंने इस बात पर खेद व्यक्त किया कि विज्ञान और ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में प्रगति और मानव के पास सब कुछ होने के बावजूद दुनिया में अभी भी झगड़े जारी हैं।

भागवत ने कहा कि भारत दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगा

भागवत ने कहा कि भारत दुनिया को एक नया रास्ता दिखाएगाऔर जहां दुनिया उसे गुरु कहेगी, वहीं भारत उसे मित्र कहेगा। वह नागपुर में आर्ट आफ लिविंग द्वारा आयोजित कार्यक्रम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग महा रुद्र पूजा में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। आरएसएस प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि मानव जीवन एक गहरे अपनेपन की भावना पर आधारित है और आज विश्व इसी रिश्ते के लिए तरस रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 2,000 वर्षों में दुनिया जिस प्रवाह में चली, वह प्रवाह अधूरी चीजों पर आधारित था। इसलिए वे सोचते हैं कि हर कोई अलग है और हर किसी का अपना हित है और जो शक्तिशाली हैं वे अपने हितों को प्राप्त करेंगे और जो कमजोर हैं वे मर जाएंगे। यही दुनिया का नियम है, यही वे सोचते हैं। आरएसएस प्रमुख ने उपस्थित लोगों से कहा, "हम देखते हैं कि विज्ञान और मानव ज्ञान में प्रगति के बावजूद झगड़े अभी भी जारी हैं और मनुष्य सब कुछ पाकर भी असंतुष्ट है।

'भारत-अमेरिका व्यापार समझौते नवंबर तक अंतिम रूप ले लेगा'

जिस तरह से वार्ता आगे बढ़ रही है, उससे दोनों पक्ष संतुष्ट हैं: गोयल

नई दिल्ली/पटना

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का पहला चरण नवंबर तक अंतिम रूप ले लेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से वार्ता आगे बढ़ रही है, उससे दोनों पक्ष संतुष्ट हैं। गोयल ने बिहार की राजधानी पटना में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस को सबोधित करते हुए कहा कि व्यापार समझौते को नवंबर तक अंतिम रूप दे दिया जाएगा। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता आगे बढ़ रही है, जिसकी पुष्टि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने की है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री की ये टिप्पणी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच सोशल मीडिया पर सकारात्मक बातचीत के एक दिन बाद आई है। उन्होंने कहा कि इसी साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दोनों ने अपने मंत्रियों को नवंबर तक समझौते के पहले भाग को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया था। आयोजित कार्यक्रम में यही बात दोहराई थी।

अमेरिका-न्यूजीलैंड के साथ सक्रिय रूप से चर्चा

भारत संभावित व्यापार समझौतों के लिए अमेरिका और न्यूजीलैंड के साथ सक्रिय रूप से चर्चा कर रहा है। इस बीच, अमेरिका से वातार्काकारों का एक दल इस महीने के अंत तक भारत का दौरा करेगा और नवंबर तक द्विपक्षीय व्यापार समझौते (बीटीए) पर हस्ताक्षर कर दिए जाएंगे। भारत के मुख्य वातार्काकार राजेश मल्होत्रा, व्यापार समझौते के विभिन्न मानदंडों पर काम कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि इस बातचीत से नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच तनाव कम होने के संकेत मिले हैं।

हाइड्रोजन बम आएगा, सारा का सारा साफ हो जाएगा: राहुल

रायबरेली

कांग्रेस नेता राहुल गांधी दो दिवसीय दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली में हैं। बृहस्पतिवार को दिशा की बैठक में शामिल होने के बाद जब वो बाहर निकले तो मीडिया को बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग बहुत आंदोलित हो रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब हाइड्रोजन बम आएगा तो सब साफ हो जाएगा।

नेपाल की जेल से भागे कैदियों पर एसएसबी का शिकंजा, 35 गिरफ्तार

नई दिल्ली

भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नेपाल के जेलों से फरार हुए 35 कैदियों को धर दबोचा है। ये कैदी नेपाल में हाल के अशांति और दंगों के बीच जेलों से भाग निकले थे। एसएसबी ने उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में इन फरार कैदियों को सीमा पार करने की कोशिश करते हुए पकड़ा।

'वर्दी पहनने के बाद जाति और धर्म से ऊपर उठकर काम करें'

नई दिल्ली

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के अकोला में मई 2023 में हुए सांप्रदायिक दंगों की जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठन करने का आदेश दिया है। इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के वरिष्ठ पुलिस अफसर शामिल होंगे। कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस की "पक्षपातपूर्ण" जांच पर सख्त नाराजगी जताई और कहा कि पुलिस का काम बिना किसी धर्म या जाति के भेदभाव के कानून के मुताबिक निष्पक्ष जांच करना है। यह आदेश 17 साल के मोहम्मद अफजल मोहम्मद शरीफ की याचिका पर आया, जिन्होंने दंगों में हमले का

शिकार होने के बावजूद पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाया। अकोला में मई 2023 में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर भड़के दंगों में एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि आठ लोग, जिनमें दो पुलिसवाले शामिल थे, घायल हुए थे।

दंतेवाड़ा में आईईडी विस्फोट , सीआरपीएफ के दो जवान घायल

दंतेवाड़ा

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा जिले के थाना मालेवाही क्षेत्रांतर्गत सीआरपीएफ 195वीं वाहिनी के जवान मुख्यालय से सातधार एवं मालेवाही की ओर रवाना हुए थे। अभियान के दौरान आज गुरूवार को करीब 11 बजे सातधार पुल से आगे नक्सलियों द्वारा लगाए गये प्रेशर आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के दो जवान निरी. दीवान सिंह गुर्जर एवं आरक्षक आलम मुनेश घायल हो गए । दंतेवाड़ा एसपी गौरव राय ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि प्राथमिक उपचार उपचार के बाद घायल जवानों को घटनास्थल से सुरक्षित निकालकर बेहतर चिकित्सा सुविधा हेतु उच्चतर चिकित्सा केंद्र के लिए रवाना किया गया है। घायल जवानों की स्थिति सामान्य है, तथा वे खतरे से बाहर हैं। अभियान पूर्ण होने के पश्चात विस्तृत विवरण पृथक से जारी किया जाएगा। वहीं, इलाके में सर्चिंग शुरू कर दिया गया है।

देश की शून्य सहनशीलता की नीति को मजबूत करेंगे- उपराज्यपाल सिन्हा

श्रीनगर

जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुवार को कहा कि भारत के नए आपराधिक कानून आतंकवाद के प्रति देश की शून्य सहनशीलता की नीति को मजबूत करेंगे और समाज से आतंकवाद को खत्म करने में मदद करेंगे। जेएंडके पुलिस पब्लिक स्कूल बेमिना में बोलते हुए उपराज्यपाल सिन्हा ने कहा कि नए कानूनों ने लगभग 150 वर्षों के बाद औपनिवेशिक काल के आपराधिक न्याय नियमों की जगह ले ली है। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक बदलाव है जो भारत की न्याय व्यवस्था को औपनिवेशिक शासन के अवशेषों से मुक्त करता है और कमजोर समूहों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता है।

सिन्हा ने कहा कि इन तीन कानूनों ने हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया है और अब सिर्फ. सजा के बजाय पीड़ितों पर ध्यान केंद्रित किया है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया 2019 में शुरू हुई जब प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटिश काल के सभी कानूनों की समीक्षा का आदेश दिया। तब से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से नए कानून बनाने के लिए प्रतिक्रियाएँ एकत्र की गईं जिनका उद्देश्य सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करना है।

हरियाणा के किसानों की मांग, बाढ़ में आई रेत का मिले मालिकाना हक

बीकेयू नेताओं ने मुख्यमंत्री के साथ की बैठक, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 50 हजार रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की मांग

चंडीगढ़

हरियाणा के किसानों ने भी अब पंजाब की तर्ज पर जिसका खेत, उसकी रेत योजना लागू करने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में किसानों का एक शिष्टमंडल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी से मिला। बुधवार की रात सीएम आवास पर हुई बैठक में हरियाणा के किसानों ने बाढ़ के कारण खेतों में आए रेत के मालिकाना हक किसानों को देने की मांग की। बीकेयू प्रवक्ता राकेश बैंस ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा के 5200 गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। किसान नेताओं ने राज्य में धान की खरीद 15 सितंबर से शुरू किए जाने की मांग करते हुए सीएम से कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए मुआवजा राशि पचास हजार की जाए। बाढ़ के कारण किसानों को जो ट्यूबबेल खराब हुए हैं, उनका मुआवजा दिया जाए। किसानों ने बरसाती नालों, नदियों की सफाई करवाने तथा तटीय बांधों पॅकी मरम्मत करवाए जाने की मांग करते हुए कहा कि चीका हल्का में हांसी बुटाना नहर के कारण घग्गर नदी बाढ़ का कारण बनती है। उस पर ध्यान दिया जाए। यूरिया खाद वितरण पोर्टल पर होने से किसानों को खाद लेने में भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसे तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। कपास की पूरी खरीद सरकार के माध्यम से करवाए जाने की मांग करते हुए बीकेयू नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों बीमा का मुआवजा देने का कानून लाया जाए। किसानों ने गन्ने की एमएसपी पांच सौ रुपये प्रति क्विंटल किए जाने की मांग करते हुए कहा कि बिजली के जो बड़े टावर किसानों के खेतों से निकलते हैं वह एक राज्य से दूसरी स्टेट में जा रहे हैं।

उसका मुआवजा किसानों को दिया जाना चाहिए।

पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के लिए तीसरा राहत सामग्री का ट्रक रवाना

सोनीपत

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली ने गुरुवार को हरियाणा के सोनीपत जिले के सेक्टर-7 स्थित पार्टी कार्यालय से पंजाब के बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत सामग्री से भरा ट्रक रवाना किया। यह ट्रक गुरदासपुर जिले में भेजा गया है, जहां हाल की भारी बारिश और बाढ़ ने हजारों लोगों को प्रभावित किया है। सोनीपत जिले से यह तीसरा ट्रक है, जिसे पीड़ितों की मदद के लिए भेजा गया। मोहनलाल बडौली ने बताया कि ट्रक में 500 खाद्य पैकेट, 500 मेडिकल किट और 500 तिरपाल शामिल हैं। खाद्य पैकेट में आटा, दाल, चावल, चीनी, हल्दी और अन्य जरूरी सामान रखा गया है।

दस साल में कितने कर्मचारी हुए नियमित, विभागों से मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में चल रहा केस, दो दिन रिपोर्ट देंगे विभागाध्यक्ष

चंडीगढ़

सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केस के मद्देनजर हरियाणा सरकार ने सभी विभागों से दो दिन के भीतर पिछले दस साल में स्थाई किए गए कर्मचारियों का ब्यौरा मांग लिया है। सरकार ने यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में लंबित स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम योगेश त्यागी केस को लेकर की है। विभागाध्यक्षों को इसकी जानकारी 12 सितंबर तक भेजनी होगी। मानव संसाधन विभाग द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि 28 जुलाई 2025 को हुई पिछली सुनवाई में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत करने को कहा था। इससे पहले 95 विभागों, बोर्डों और निगमों की रिपोर्ट महाधिवक्ता कार्यालय, चंडीगढ़ को भेजी जा चुकी है। अब अदालत ने दोबारा अपडेटेड डेटा मांगा है। विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों और उपायुक्तों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने पुराने आंकड़ों में कोई बदलाव है तो उसे अपडेट करें और तुरंत भेजें। जानकारी न होने की स्थिति में भी शून्य सूचना अनिवार्य रूप से भेजनी होगी। सभी विभागों को यह रिपोर्ट मानव संसाधन-1 शाखा को ई-मेल के माध्यम से भेजनी है। सरकार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगर समयसीमा का पालन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे।

हिमाचल में भारी बारिश का अलर्ट, कुल्लू में नदी में फंसे दो लोगों का रेस्क्यू

शिमला

हिमाचल प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है और मौसम विभाग ने अगले तीन दिन के लिए राज्य में भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। इस बीच कुल्लू जिले के कराड़सु विहाल में नदी के बीच फंसे दो लोगों को पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने सुरक्षित रेस्क्यू किया है। पुलिस थाना सदर कुल्लू के प्रभारी अजय और एनडीआरएफ टीम के अनुसार दोनों व्यक्तियों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 12 से 14 सितंबर तक राज्य के अधिकांश जिलों में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी और सोलन जिलों में आज ऑरेंज अलर्ट जारी है, जबकि 12 से 14 सितंबर तक ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। 15 और 16 सितंबर को हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है, लेकिन किसी प्रकार का अलर्ट नहीं है। पिछली रात से सुबह तक कई स्थानों पर अच्छी खासी बारिश दर्ज की गई। मंडी जिले की मुरारी देवी में 63 मिमी, हमीरपुर के भरेड़ी में 62 मिमी, बिलासपुर के सलापड़ में 54 मिमी और नैना देवी में 42 मिमी वर्षा हुई। लगातार बारिश से सड़क मार्ग, बिजली और पानी की आपूर्ति ठप हो गई है। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार प्रदेश में गुरुवार सुबह तक तीन नेशनल हाइवे और 574 सड़कें बंद रहीं।

अगस्त में 3 लाख वाहन स्क्रैप, बीएस-7 मानदंडों के साथ वैश्विक स्टैंडर्ड अपनाएंगे: गडकरी

नई दिल्ली

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिए वरदान साबित हो रही है। अगस्त 2025 तक 3 लाख वाहन स्क्रैप हो चुके हैं, जिनमें से 1 लाख 41 हजार सरकारी वाहन थे, जबकि देश में 97.4 लाख वाहनों को स्क्रैप किया जा सकता है। गडकरी ने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) के 65वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से स्क्रैपिंग के बाद नई गाड़ियां खरीदने वाले लोगों को जीएसटी में राहत देने का अनुरोध किया है। वर्तमान में मासिक 16,830 वाहन स्क्रैप हो रहे हैं और निजी क्षेत्र ने इस क्षेत्र में 2,700 करोड़ रुपये का निवेश किया है। भारत प्रतिवर्ष 27 लाख टन स्टील आयात करता है, जो स्क्रैपिंग से प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह एल्यूमीनियम का आयात भी कम हो सकता है। स्क्रैपिंग से अब तक 3.67 लाख टन स्टील निकाला गया है, जो कुल जरूरत का मात्र 6 प्रतिशत है।

यदि स्क्रैप धातुओं से नई गाड़ियां बनाई जाएं तो केंद्र और राज्य सरकारों को 40 हजार करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होगा, साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी लागत में भारी कमी का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने बीएस-4 से बीएस-6 उत्सर्जन मानदंडों पर पहुंच गया है, जो सभी पक्षों के समन्वय का परिणाम है। अब बीएस-7 मानदंडों और कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (कैफे) को अपनाने के लिए वैश्विक मानकों, विशेष रूप से यूरोपीय स्टैंडर्ड्स के साथ तालमेल बनाए रखा जाएगा।

'विदेश यात्राओं पर राहुल ने किया सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन, यह चिंता का विषय'

सीआरपीएफ का खरगे को खत

नई दिल्ली

केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को पत्र लिखकर पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी की ओर से पिछली विदेश यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल के उल्लंघन का जिक्र किया है। सीएपीएफ ने राहुल गांधी को भी एक अलग पत्र लिखकर इस मामले से अवगत कराया है। सीआरपीएफ ने कहा है कि उनकी सुरक्षा को देखते हुए यह गंभीर चिंता का विषय है।

राहुल को उच्चतम स्तर की 'जेड+' सुरक्षा प्राप्त

पत्र में कहा गया है कि राहुल को एडवांस सिक्योरिटी लाइजन (एएसएल) कवर के साथ उच्चतम स्तर की 'जेड+' सुरक्षा प्राप्त है। उन्होंने कई मौकों पर अनिवार्य सुरक्षात्मक उपायों का पालन करने में समर्थता जताई। सीआरपीएफ ने हाल ही में राहुल और खरगे दोनों को भेजे गए पत्र में कहा कि इस तरह की चूक वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की प्रभावशीलता को कमजोर करती है और उन्हें संभावित जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना सकती है। भविष्य की यात्राओं के दौरान **सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की अपील**

सूत्रों ने मुताबिक, सीआरपीएफ ने 10 सितंबर को दोनों नेताओं को भेजे गए अलग-अलग पत्रों में यह मुद्दा उठाया और भविष्य की यात्राओं के दौरान सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने की अपील की। अपने पत्र में सीआरपीएफ ने राहुल गांधी की इटली, वियतनाम, दुबई, कतर, लंदन और मलेशिया जैसे देशों की विदेश यात्राओं का जिक्र किया।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10000 की भरण पोषण सीमा बढ़ाई जाए: कर्नाटक हाईकोर्ट

"माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के लिए तय 10 हजार रुपये प्रतिमाह की राशि की सीमा बढ़ाए। क्योंकि यह आज की महंगाई दर को देखते हुए उपयुक्त नहीं है"

बंगलूरू

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण के लिए तय 10 हजार रुपये प्रतिमाह की राशि की सीमा बढ़ाए। क्योंकि यह आज की महंगाई दर को देखते हुए उपयुक्त नहीं है। कोर्ट ने केंद्र से माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 9 की समीक्षा और संशोधन करने की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह सीमा आज की आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप नहीं है। इसे महंगाई के अनुसार बदलने की जरूरत है। कोर्ट यह सिफारिश करना उचित समझता है कि केंद्र धारा 9 पर पुनर्विचार करे और जीवन-यापन सूचकांक की लागत के अनुरूप अधिकतम सीमा को संशोधित करे। ताकि यह अधिनियम एक खोखला वादा बनकर न रह जाए, बल्कि वृद्धावस्था में सम्मान की जीवंत गारंटी बना रहे। पीठ ने कहा कि किसी राष्ट्र की सच्ची संपदा का मापदंड केवल भौतिक प्रगति नहीं बल्कि इस बात से भी होता है कि वह अपने बच्चों और बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है। 2007 से जीवन-यापन की लागत में भारी वृद्धि हुई है। 10,000 रुपये की वैधानिक सीमा समय के साथ अस्थिर बनी हुई है।

अदालत ने सरकार के मुद्रास्फीति सूचकांक का हवाला देते हुए कहा कि जो चीज 2007 में 100 रुपये में खरीदी जा सकती थी, उसके लिए 2025 में लगभग 1,000 रुपये की जरूरत होगी। भोजन, आवास और स्वास्थ्य सेवा का खर्च कई गुना बढ़ गया है। फिर भी भरण पोषण की सीमा में बदलाव नहीं हुआ है। इससे बुनियादी जरूरतें भी पूरी करना असंभव हो गया है। पीठ ने सवाल उठाया कि क्या इतनी कम सहायता से सम्मान और चिकित्सा देखभाल मिल सकेगी। कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस वास्तविकता की अनदेखी करने से वृद्धावस्था मात्र एक पशुवत अस्तित्व बनकर रह जाएगी।

'17 सितंबर से शुरू होगा सेवा पखवाड़ा, स्वच्छता-सेवा के मूल्यों को मिलेगा बल'

नई दिल्ली

केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को सेवा पखवाड़ा को लेकर अहम जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि आने वाले 17 सितंबर से 2 अक्तूबर तक पूरे देश में भाजपा 'सेवा पखवाड़ा' आयोजित करेगी। यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) से शुरू होगा। पत्रकारों से बातचीत के दौरान भूपेंद्र यादव ने बताया कि पीएम मोदी ने भारतीय राजनीति में सेवा, स्वच्छता और संवेदनशीलता जैसे मूल्यों को मजबूत किया है। चाहे संकट हो, महामारी हो या प्राकृतिक आपदा उन्होंने हमेशा सेवा भाव से लोगों को जोड़ने की प्रेरणा दी है।

गांवों तक पहुंचाया जाएगा स्वच्छ पानी

केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने आगे सेवा पखवाड़ा के दौरान होने वाले कामों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में दूर-दराज के गांवों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाया गया है और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को लेकर देश मजबूत कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि सेवा पखवाड़े के दौरान स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वास्थ्य सेवा और जनकल्याण से जुड़ी विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएंगी, जिससे समाज के हर वर्ग के लोग इससे जुड़ सकें।

इंदौर-भोपाल से नागपुर का सफर होगा आसान, 16 कोच के साथ चलेगी वंदे भारत

नई दिल्ली

मध्यप्रदेश के इंदौर और भोपाल से नागपुर के बीच सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे का रतलाम मंडल इंदौर-नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को अपग्रेड करने के साथ ही इसे अब आठ की जगह 16 कोच के साथ चलाने जा रहा है। रतलाम मंडल के एक वरिष्ठ ने बताया कि संभवतः अक्टूबर के पहले सप्ताह से 16 कोच के साथ इंदौर-नागपुर वंदे भारत ट्रेन चलेगी।

दरअसल, इंदौर से भोपाल होकर नागपुर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन में कोच बढ़ाने का निर्णय रेलवे बोर्ड की कमेटी ने लिया है। इस रूट पर यात्रियों की लगातार बढ़ती मांग और त्योहारी सीजन को देखते हुए रेलवे ने इस रूट पर अतिरिक्त कोच जोड़ने का फैसला लिया है।

सियासी संग्राम: मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर पहुंचे संजय सिंह

पुलिस ने किया नजरबंद

श्रीनगर

आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर पहुंचे आप सांसद संजय सिंह को सरकारी गेस्ट में नजरबंद कर दिया गया। इससे जम्मू-कश्मीर में सियासी पारा चढ़ गया है। संजय सिंह ने कहा कि 'तानाशाही चरम पर है। मैं इस समय श्रीनगर में हूं। लोकतंत्र में हक के लिए आवाज उठाना आंदोलन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है।' वहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस (नेकॉ) के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला आप सांसद संजय सिंह से मिलने पहुंचे हैं। आप सांसद संजय सिंह ने आगे कहा कि 'आज मेहराज मलिक की अवैध गिरफ्तारी के खिलाफ श्रीनगर में प्रेस कांफ्रेंस और धरना था, लेकिन सरकारी गेस्ट हाउस को पुलिस छावनी बना दिया गया है। मुझे और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे इमरान हुसैन और अन्य साथियों को गेस्ट हाउस से बाहर निकलने की इजाजत नहीं दी गई।'

यह है मामला

विधायक मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के मुद्दे पर जम्मू-कश्मीर के डोडा में तनावपूर्ण शांति है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने मंगलवार रात से निषेधाज्ञा लागू कर दी थी। बुधवार को इन प्रतिबंधों का दायरा भद्रवाह तक बढ़ा दिया गया था। इस बीच, जम्मू पहुंचे पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मेहराज की पीएसए के तहत गिरफ्तारी को अवैध और असंवैधानिक करार दिया।

मेहराज पर ये आरोप

मेहराज मलिक पर अफवाह फैलाने, आतंकियों का महिमामंडन करने, महिलाओं के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने, डोडा के उपायुक्त हरविंदर सिंह को अपशब्द कहने और सरकारी अस्पताल के कार्य में बाधा डालने के आरोप हैं। उन्हें आठ सितंबर को पीएसए के तहत गिरफ्तार कर कठुआ जिला जेल भेज दिया गया। इसके बाद उनके समर्थकों ने डोडा जिले में कई जगह उग्र प्रदर्शन किए। पुलिस पर पथराव किया। इसमें दो अधिकारियों सहित कम से कम आठ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। पुलिस से झड़प में पांच प्रदर्शनकारी भी जख्मी हुए थे।

भारत-पाक एशिया कप मैच पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

नई दिल्ली

उच्चतम न्यायालय ने भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के लिए आगामी 14 सितंबर को होने वाले क्रिकेट मैच पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। जस्टिस जेके माहेश्वरी की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि इसके लिए जल्दबाजी क्या है। मैच को लेकर ऊर्वशी जैन समेत चार लोगों ने याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट के समक्ष मेंशन करते हुए इस याचिका पर 12 सितंबर को सुनवाई करने की मांग की है। तब कोर्ट ने कहा कि इसमें जल्दबाजी क्या है, मैच होने दीजिए। तब याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि मैच 14 सितंबर को है जिस दिन रविवार है। अगर इस याचिका पर 12 सितंबर को सुनवाई नहीं होगी, तो ये याचिका औचित्यहीन हो जाएगी। तब कोर्ट ने कहा कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, मैच होने दीजिए। तब वकील ने कहा कि मेरा केस खराब या अच्छा हो सकता है लेकिन कम से कम लिस्ट तो हो। लेकिन जस्टिस माहेश्वरी ने आग्रह को अस्वीकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि हर रोज एक पक्ष या दूसरा पक्ष खेलता है। दायर याचिका में कहा गया था कि एक तरफ हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं और दूसरी तरफ हम उस देश से मैच खेल रहे हैं, जो देश के खिलाफ आतंकी कार्रवाई करने वालों का पनाहगाह हो।

दिल्ली मेट्रो, नमो भारत कॉरिडोर और सड़क व स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात मिलेगी।

दिल्ली वालों को मिलेगी कई परियोजनाओं की सौगात

चार अन्य अस्पतालों में अतिरिक्त भवन निर्माण से जुड़ी परियोजनाएं पूरी हो गई

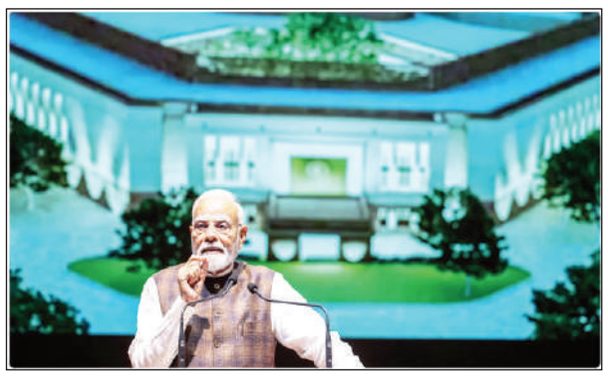

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर को दिल्ली मेट्रो, नमो भारत कॉरिडोर और सड़क व स्वास्थ्य से जुड़ी कई परियोजनाओं की सौगात मिलेगी। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो के फेज-चार के तहत पिंक लाइन का विस्तार, नमो भारत का सराय काले खां स्टेशन, वजीराबाद रोड पर फ्लाईओवर और चार अन्य अस्पतालों में अतिरिक्त भवन निर्माण से जुड़ी परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं को पीएम के जन्मदिन पर जनता के लिए शुरू किया जा सकता है। परियोजनाओं के शुरू होने से राजधानी की कनेक्टिविटी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा। वहीं, अस्पताल में बेड की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। वर्तमान में नमो भारत दिल्ली के न्यू अशोक नगर से दुहाई डिपो तक पहले से ही चालू है। अब पूरा 82 किलोमीटर का कॉरिडोर चालू होने से दिल्ली से मेरठ के बीच का सफर महज एक घंटे से भी कम में तय किया जा सकेगा। इसमें अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ट्रेनें, हाई-स्पीड यात्रा और बेहतर सुरक्षा इंतजाम होंगे। इससे दिल्ली-एनसीआर के लाखों यात्रियों को न केवल समय की बचत होगी बल्कि सड़क और निजी वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी।

पिंक लाइन विस्तार बनेगी नई पहचान...

दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन का मौजूदा नेटवर्क माजलिस पार्क से मयूर विहार पॉकेट-1 तक है। 12.3 किलोमीटर लंबे इस विस्तार के पूरा होने से माजलिस पार्क से मौजपुर तक सीधा सफर संभव हो जाएगा। इस हिस्से का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके शुरू होने के बाद पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी कॉरिडोर बन जाएगी, जो राजधानी के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी इलाकों को जोड़ेगी। इससे विशेषकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों को सीधा लाभ होगा और मेट्रो यात्रा और भी आसान बनेगी।

चार अस्पतालों के अतिरिक्त भवन तैयार

राजधानी में स्वास्थ्य से जुड़ी चार परियोजनाओं का भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसमें आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल में 270 नए बेड, दादा देव मातृ एंव शिशु चिकित्सालय 180 नए बेड, गुरु गोबिंद सिंह अस्पताल में 472 नए बेड और संजय गांधी अस्पताल ट्रामा सेंटर में 362 नए बेड के भवन शामिल हैं।

गगन सिनेमा फ्लाईओवर भी बनकर तैयार...

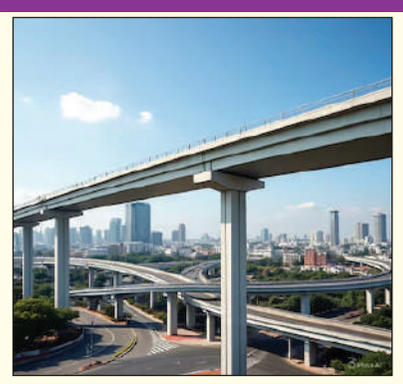

दिल्ली इन अस्पतालों के नए भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर पर शुरू करने की योजना बना रही है। सिग्नेचर ब्रिज से गाजियाबाद के भोपुरा को जाने वाली वजीराबाद रोड स्थित गगन सिनेमा फ्लाईओवर का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। पूर्व की आप सरकार के समय शुरू हुआ यह निर्माण कार्य वजीराबाद रोड को सिग्नल फ्री करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बीते माह दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने कहा था कि इस फ्लाईओवर का पीएम के जन्मदिन पर जनता के लिए शुरू किया जाएगा। इसके शुरू हो जाने से शहीद मंगल पांडे मार्ग पर वजीराबाद से भोपुरा बार्डर के बीच आ रही केवल गगन सिनेमा की लालबत्ती खत्म हो जाएगी।

दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन का मौजूदा नेटवर्क माजलिस पार्क से मयूर विहार पॉकेट-1 तक है। 12.3 किलोमीटर लंबे इस विस्तार के पूरा होने से माजलिस पार्क से मौजपुर तक सीधा सफर संभव हो जाएगा। इस हिस्से का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके शुरू होने के बाद पिंक लाइन दिल्ली मेट्रो की सबसे लंबी कॉरिडोर बन जाएगी, जो राजधानी के उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी इलाकों को जोड़ेगी। इससे विशेषकर उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोगों को सीधा लाभ होगा और मेट्रो यात्रा और भी आसान बनेगी।

आतंकी गिरोह का लीडर है दानिश, कोड नाम था सीईओ

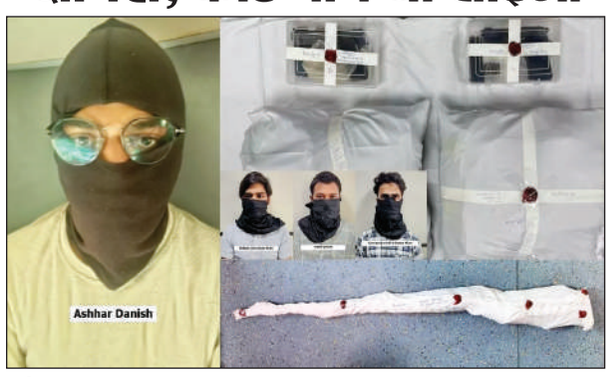

नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकियों की साजिश को नाकाम किया है। स्पेशल सेल ने इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) की सूचना पर पांच आतंकियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार, एक आतंकी को दिल्ली, एक को मध्य प्रदेश और एक हैदराबाद समेत पांच को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और एजेंसियां अभी भी संदिग्ध आतंकियों की तलाश के छापामारी कर रही है।

गिरोह का लीडर निकला दानिश

पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, गिरोह के लीडर की पहचान दानिश के रूप में हुई है। वह मॉड्यूल गजवा का लीडर था। उसका कोड नाम सीईओ था। पुलिस ने आतंकियों के कब्जे से भारी मात्रा में आईईडी ब्लास्ट में इस्तेमाल होने वाला बारूद व अन्य संदिग्ध सामान और हथियार बरामद किए हैं।

पुलिस की जांच में पाक हैंडलर आधारित पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। बताया कि एक झारखंड, दो दिल्ली, एक तेलंगाना और एक मध्य प्रदेश के राजगढ़ से गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आतंकियों की पहचान लीडर अशरफ दानिश, टारगेट किलर आफताब अंसारी, सूफियान अबु बकर, कामरान कुरैशी और उजैफा के रूप में हुई है। इनमें से कोई भी अभी तक पाकिस्तान नहीं गया है लेकिन, ये पाक हैंडलर गिरोह है।

चुनावी उम्मीदवारों के खर्च मामले से जुड़ी याचिका पर विचार करने से इनकार

नई दिल्ली

दिल्ली में चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों और चुनावी उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय करने सहित अन्य सुधारों की मांग वाली जनहित याचिका पर विचार करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि यह मुद्दा पहले से ही सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

कोर्ट ने कहा कि नीतिगत मामले में अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। वहीं, निर्वाचन आयोग को निर्देश जारी करने से इनकार

करते हुए अदालत ने याचिकाकर्ता को सक्षम प्राधिकारियों के समक्ष अभ्यावेदन देने की अनुमति दी और याचिका का निपटारा कर दिया।

वायु सेना के अधिकारी की पत्नी से ठगी, तांत्रिक की सच्चाई जान उड़े पुलिस अफसरों के होश

धार्मिक अनुष्ठान और पूजा कराने के बहाने 1.14 लाख रुपये ठग लिए

नई दिल्ली

दिल्ली में घर में बुरी आत्मा का साया होने का डर दिखाकर वायु सेना अधिकारी की पत्नी से एक तांत्रिक ने धार्मिक अनुष्ठान और पूजा कराने के बहाने 1.14 लाख रुपये ठग लिए। पैसे मिलने के बाद आरोपी ने महिला का फोन उठाना बंद कर दिया, तब उसे लगा कि जालसाजी हुई है। इसके बाद उन्होंने नई दिल्ली के साइबर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है। पुलिस अधिकारी के मुताबिक, मनीषा जिलोया गृहणी हैं और अपने परिवार के साथ चाणक्यपुरी के तेजस कैंपस में रहती हैं। उनके पति नवीन जिलोया भारतीय वायु सेना में अधिकारी हैं। मनीषा ने चार सितंबर को साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ माह से उनके पति और बच्चों को शारीरिक चोट लग रही थी और अन्य घरेलू समस्याएं भी सामने आ रही थीं। एक दिन इंस्टग्राम पर उन्हें

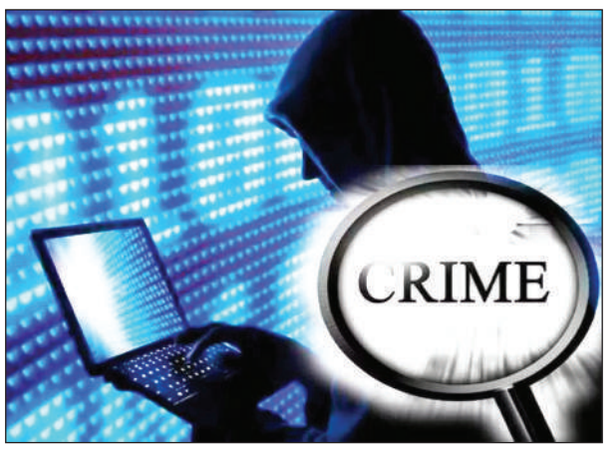

अघोरी राजस्थान नाम से एक लिंक मिला, जिसमें वीडियो डालने वाले ने खुद को तांत्रिक बताया था। उसके पेज पर व्यक्तिगत और परिवारिक मुद्दों के लिए आध्यात्मिक उपचार करने की बात लिखी हुई थी। उसके प्रोफाइल पर एक मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ था। उसने सारी समस्याओं का समाधान करने का भी भरोसा दिया था। मनीषा ने दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क किया तो उसने अगले दिन उन्हें बताया कि उनके घर में बुरी आत्मा का साया है, जो उन्हें और परिवार को कष्ट दे रही है। इस समस्या से निजात दिलाने के लिए उसने पूजा और धार्मिक अनुष्ठान कराने की बात कही।

आरोपी ने बताया कि पूजा और अनुष्ठान कराने पर करीब एक लाख 14 हजार रुपये खर्च होंगे। मनीषा को उसने एक क्यूआर कोड भेजा। मनीषा ने भरोसा करके उस क्यूआर कोड पर रकम ट्रांसफर कर दी। पैसा मिलने के बाद उसने मनीषा का मोबाइल उठाना बंद कर दिया और मैसेज का भी जवाब नहीं दिया।

इसके बाद उन्होंने छह सितंबर को साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस इंस्टाग्राम और बैंक अकाउंट की मदद से आरोपी का पता लगाने का प्रयास कर रही है।

मुठभेड़ में दबोचा शॉर्प-शूटर राहुल, फरवरी में वारदात को दिया था अंजाम

27 फरवरी को बहालगढ़ में गांव भांजा की 14 गोली मारकर हत्या की थी

नई दिल्ली/(सोनीपत)

सोनीपत जिले के गोहाना में एसटीएफ करनाल की टीम ने दीपक हत्याकांड में संलिप्त शॉर्प-शूटर गांव गुढ़ा के राहुल को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ को राहुल के गोहाना में होने का इनपुट मिला था और वह किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। टीम जब उसे काबू करने रोहतक-पानीपत हाईवे स्थित बड़ौता बाईपास के पास पहुंची तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे काबू कर लिया गया।

बताया गया कि बदमाश को भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कालेज के अस्पताल ले जाया गया। राहुल पानीपत के कुख्यात गैंगस्टर राकेश उर्फ पंपू गैंग से जुड़ा है।

बाढ़ का असर, लोगों का काम-धंधा हुआ बंद; अब गाद से लड़ी जा रही जंग

गाद और गंदगी से जूझते यमुना किनारे के लोग, घरों में जमा कीचड़, सफाई में जुटे

नई दिल्ली

यमुना का जलस्तर नीचे जाने के बाद भी नदी किनारे रहने वाले लोगों की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाढ़ का पानी उतर चुका है, लेकिन निचले इलाकों में अब गाद-गंदगी और दुर्गंध से लोग जंग लड़ी जा रही है।

हालत यह है कि लोगों के घरों और गलियों में अब भी दो से तीन फीट तक कीचड़ और गाद जमा है। इसे हटाने के लिए पूरा परिवार काम-धंधा सब छोड़कर दिनभर गाद निकालने में लगा रहता है। जिन परिवारों में एक ही व्यक्ति कमाई करने वाला है, उसके लिए बड़ी दिक्कत है। कुल मिलाकर अभी इन लोगों की जिंदगी बिल्कुल अस्त-व्यस्त है। इसे पटरी पर लौटने में समय लगेगा। यमुना बाजार, सिग्नेचर ब्रिज के नीचे और राजघाट रोड पर स्थिति बेहद चिंताजनक है। बुधवार को यमुना बाजार के घाट नंबर-24 और उससे लगी गली से स्थानीय लोग कीचड़ हटाने का प्रयास करते दिखे। इस दौरान सांप भी निकल रहे थे। लोगों का कहना है कि प्रशासन उनकी कोई मदद नहीं कर रहा है।

बदबू से भरी गलियों में चारपाई पर पढ़ाई...

यमुना बाजार इलाके में बाढ़ आने के बाद से अधिकांश स्कूल बंद चल रहे हैं। उस समय बच्चे परिवार के साथ राहत शिविरों में रहने चले गए थे। वहां से लौटने के बाद वे भी परिवार के साथ दिनभर गाद निकालते रहते हैं। बीच में जब समय मिलता है तो घर के बाहर डाली गई चारपाई पर बैठकर वे पढ़ाई करते हैं। घर की सफाई करते-करते जब महिलाएं थक जाती हैं, तो वे भी आराम करने के लिए बाहर पढ़ रहे बच्चों के पास बैठ जाती हैं। गली भी गाद और कीचड़ से भरी हुई है, जिससे वहां दुर्गंध भी आती रहती है, लेकिन घर के अंदर से बाहर वे कुछ बेहतर महसूस करती हैं।

कीचड़ और गाद हटाते समय इसमें से जहरीले सांप और कीड़े-मकोड़े निकलते हैं, जो उनको काट सकते हैं। इसलिए उनकी मांग है कि सरकार इसे मशीन से साफ करवाए। निचले इलाकों में मच्छरों का प्रकोप भी बहुत बढ़ गया है। इसलिए लोग चाहते हैं कि प्रशासन यहां फागिंग करवाए।

युवक की पीटकर हत्या, दिल्ली पुलिस ने छह को किया गिरफ्तार

नई दिल्ली

रोहिणी जिला के प्रेम नगर स्थित किराड़ी इलाके में झगड़ा कर रहे दो पड़ोसियों के बीच विवाद सुलटाने पहुंचे पड़ोसी सुनील कुमार (42) की एक पक्ष ने लाठी-डंडे से पीटकर जान ले ली। झगड़े में पड़ोसी बुजुर्ग आनंद कुमार (60) भी जख्मी हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। आनंद विहार और उनकी पत्नी सुमित्रा और रिश्तेदार महिला पुष्पा को गिरफ्तार कर लिया है।

एअर इंडिया के विमान में आई तकनीकी खामी, देरी से भरी उड़ान

नई दिल्ली

सिंगापुर जाने वाले एयर इंडिया के एक विमान में सवार 200 से अधिक यात्रियों को बुधवार रात दिल्ली हवाई अड्डे पर परेशानी का सामना करना पड़ा। विमान में एयर कंडीशनिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक सप्लाई में खराबी के चलते यात्रियों को फ्लाइट से उतार दिया गया। लगभग छह घंटे की देरी के बाद उन्हें उनके गंतव्य के लिए रवाना किया गया। बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान से संचालित होने वाली फ्लाइट अक2380 को बुधवार रात लगभग 11 बजे उड़ान भरनी थी। लगभग दो घंटे तक विमान में बैठे रहने के बाद, सभी यात्रियों को विमान से उतार दिया गया। विमान में मौजूद समाचार एजेंसी पीटीआई के एक पत्रकार के मुताबिक, एयर कंडीशनिंग सिस्टम और इलेक्ट्रिक सप्लाई में गड़बड़ी थी।

बवाना में दो गुटों के बीच हुई चाकूबाजी, दो लोगों की मौत

नई दिल्ली

बाहरी दिल्ली में बवाना जेजे कालोनी में दो पक्षों में हुई चाकूबाजी में तीन लोग घायल हो गए। आनन-फानन में सभी घायलों को पास के ही अस्पताल ले जाया गया। जहां हालत गंभीर देख सभी को दूसरे अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। जहां इलाज के दौरान दोनों पक्षों के दो लोगों की मौत हो गई। मृतकों की शिनाख्त रहीमुल और इमरान के रूप में हुई है।

दिल्ली जल बोर्ड के दो कर्मचारियों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा

शोरूम के बाहर गाड़ी खड़ी करने पर हुआ विवाद, कर्मचारियों ने हड़ताल की

नई दिल्ली

सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र के चौहान बांगर में दिल्ली जल बोर्ड के दो अस्थायी कर्मचारियों को सड़क पर दौड़ाकर पीटा गया। कर्मचारियों का कसूर इतना था कि उन्होंने सीवर सफाई के लिए वाहन एक कपड़ा शोरूम के बाहर खड़ा कर दिया था। आरोप है इस बात से गुस्साए शोरूम संचालक ने अपने एक साथी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। मारपीट से वाहन चालक रोजुद्दीन व हेल्पर रवि घायल हो गया। रोजुद्दीन की शिकायत पर सीलमपुर थाना ने मारपीट समेत कई धाराओं में केस दर्ज किया है। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से गुस्साए जल बोर्ड के कर्मचारियों ने बुधवार को हड़ताल की। पुलिस व विधायक चौधरी जुबैर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। रोजुद्दीन अपने परिवार के साथ बागपत में रहते हैं। वह दिल्ली जल बोर्ड में वाहन चालक हैं। उनकी ड्यूटी सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र में है। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि वह मंगलवार दोपहर 12 बजे अपने साथी कर्मचारी रवि व सन्नी के साथ चौहान बांगर की गली तीन में सीवर सफाई को गए थे।

क्या दिल्ली के इस टोल पर हो रहा नियमों का उल्लंघन?

नई दिल्ली

दिल्ली में द्वारका सेक्टर-23 में निवासी जल संरक्षण विशेषज्ञ दीवान सिंह मूल रूप से मुंडका गांव के हैं। सप्ताह में तीन से चार दिन इनका मुंडका गांव जाना होता है। जब से यूईआर (अर्बन एक्सटेंशन रोड 2) बनी, तब से द्वारका स्थित यशोभूमि से यूईआर-2 पर चढ़कर सीधे मुंडका का रुख करते हैं। मुंडका गांव से पहले इन्हें बक्करवाला से आगे रोहतक रोड के नजदीक बने यूईआर 2 के मुंडका बक्करवाला टोल को इन्हें पार करना होता है। अब हर बार

जाने या अंजाने इनके फास्टटैग अकाउंट से द्वारका से मुंडका जाने के क्रम में 235 रुपये कट रहे हैं। वापसी में भी पैसे कटते हैं। मुंडका जाने व मुंडका से लौटने पर प्रति फेरे इनके खाते से 350 रुपये की निकासी हो रही है। यह पीड़ा अकेले दीवान सिंह की नहीं है, बल्कि उपनगरी द्वारका या टोल के दोनों ओर के इलाकों में रहने वाले लोगों की है। रोजाना आवाजाही के लिए 350 रुपये खर्च होना लोगों को अखरता है। 350 रुपये का खर्चा लोगों को तब आर्थिक बोझ से ज्यादा अन्याय लगने लगता है, जब टोल के दोनों ओर का इलाका एक ही शहर का हिस्सा है।

निवासियों के आवाजाही के अधिकार का उल्लंघन है यूईआर-2 पर बना टोल

आवाजाही के अधिकार का हनन

टोल के दोनों ओर बसे गांव व कॉलोनियों में रहने वाले लोगों का कहना है कि एक ही शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में आवाजाही के लिए टोल का आवश्यक भुगतान, शहर के लोगों को संविधान प्रदत्त आवाजाही के अधिकार का उल्लंघन है। टोल का प्रविधान लोगों को आवाजाही से रोकने के लिए बनाई गई व्यवस्था लोगों को लग रही है।

पीड़ित परिवार को मिलेगा 2.5 करोड़ का मुआवजा, सड़क हादसे में हुई थी डॉक्टर की मौत

सड़क दुर्घटना में मारे गए डाक्टर के परिवार को 2.5 करोड़ रुपये का मुआवजा

नई दिल्ली

दक्षिणी दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने मई 2023 में ओखला में हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए एक डाक्टर के परिवार को 2.5 करोड़ रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए हैं। न्यायाधिकरण की पीठासीन अधिकारी शेली अरोड़ा ने कहा कि मृत्यु की स्थिति में दावेदारों के कानूनी वारिस किसी अप्रत्याशित लाभ की उम्मीद नहीं कर सकते। साथ ही दिया गया मुआवजा किसी माफी के बदले नहीं होता। बताया गया कि मृतक यासीन खान 30 वर्षीय सीनियर रेजिडेंट डाक्टर थे, जो हर महीने 1.4 लाख रुपये कमाते थे। उनके पीछे उनकी पत्नी, माता-पिता और दो नाबालिग बेटे हैं। दुर्घटना के चार महीने बाद उनका एक और बेटा पैदा हुआ।

न्यायाधिकरण ने प्रत्यक्षदर्शी की गवाही के आधार पर माना कि यह दुर्घटना बस चालक की लापरवाह ड्राइविंग से हुई।

संपादकीय

भाषाई विविधता का सौंदर्य

भारत को विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। यहां सांस्कृतिक वैविध्य का अनूठापन है। देश में संस्कृति के कई पहलू जैसे खान-पान, वेश-भूषा, रहन-सहन और बोली-भाषा में भिन्नता के स्वरूप का सौंदर्य देखने को मिलता है। भाषा किसी संस्कृति की संवाहिका होती है और यह संस्कृति के सौंदर्य को निखारती है। किसी एक भाषा को जानना वहां की पूरी संस्कृति से परिचय करना होता है। हाल के दिनों में महाराष्ट्र में भाषाई विवाद को तूल दिया गया, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठे। अभी भी बाजार में, ट्रेन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह के विवाद देखने को लगातार मिल रहे हैं। इससे पहले बंगलुरु जैसे शहर में भी स्थानीय भाषा को लेकर विवाद हो चुके हैं, जहां बहुत बड़ी आबादी वहां की मूल निवासी नहीं है। राजनीति से प्रेरित होकर तमिलनाडु सदैव हिंदी का विरोध करता रहा है। ऐसे में भाषाएं अगर एक- दूसरे की विरोधी होने लगेंगी तो वैविध्य में जो सौंदर्य रहा है, जिस वजह से भारत को विविधताओं का का अनुपम देश कहा जाता है, उस छवि को नुकसान होगा और सांस्कृतिक रूप से हम कमजोर होंगे। इसके पीछे कई कारण हैं, जिन पर चर्चा करना आवश्यक गया है।

बहुधा ऐसे विवाद राजनीति से प्रेरित होते हैं। महाराष्ट्र में हाल में जो हुआ, उसे राजनीति के लिए भाषा के कंधे का इस्तेमाल कर और उसे अस्मिता से जोड़कर सामान्य लोगों को दिग्भ्रमित करने के प्रयास के तौर पर देखा जा सकता है। लोगों को धमकाने और मारपीट करने वाले विशेष राजनीतिक दल के सक्रिय कार्यकर्ता हैं। जाहिर है कि वे सत्ता के केंद्र में नहीं करते हुए दिखना उनकी जरूरत है। सरकार जब तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ाने के लिए कह रही है तो किसी भी कारण उसका विरोध करना मानो उनका नैतिक दायित्व बन जाता है। महाराष्ट्र में पहली से पांचवीं कक्षा तक हिंदी भाषा को मराठी और अंग्रेजी बाद तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ाए जाने को लेकर यह विवाद शुरू हुआ और अब यह पूरी तरह से राजनीतिक हो चुका है। सरकार ने त्रिभाषा सूत्र को अपनाते हुए अपनी अधिसूचना में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप अनिवार्य कर दिया था। हालांकि, विवाद के बाद अनिवार्य शब्द को हटा लिया गया।

मराठी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पहली से पांचवीं कक्षा तक के लिए हिंदी को तीसरी भाषा के में पढ़ाया जाएगा। यहां एक अच्छी लिए बात यह रही कि अगर विद्यार्थी हिंदी अतिरिक्त किसी अन्य भारतीय भाषा को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें इसकी अनुमति दी जाएगी, बशर्ते ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बीस से कम न हो। हिंदी की अनिवार्यता को लेकर अन्य अस्मिताएं जागृत हो जाती हैं, लेकिन अंग्रेजी के वर्चस्व को लेकर इस तरह के विवाद प्रायः नहीं देखने को मिलते इसके पीछे एक कारण तो देश की राजनीति का बड़ा हिस्सा हिंदी क्षेत्र का है, इसलिए राजनीतिक रूप से खतरा हिंदी क्षेत्र से लगता । जबकि अंग्रेजी भारतीय भाषा न होने के कारण अस्मिता संबंधी कोई प्रश्न इससे जुड़ नहीं पाता और यही कारण है कि अंग्रेजी इस मामले में सुरक्षित रहती है।

क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर यह मुद्दा भावनाओं से भी जुड़ जाता है, इसलिए सामान्य भोले-भाले लोगों को जब यह बात कह कर प्रभावित किया जाता है कि आप अपने ही क्षेत्र में धीरे-धीरे भाषाई अल्पसंख्यक हो जाएंगे, तो उनका डर स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। डर का अपना मनोविज्ञान होता है, जो बहुत तेजी से कार्य करता है। साथ ही उनके अंदर यह भाव भी भरा जाता है कि दूसरी भाषा के लोग आपके क्षेत्र के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपकी नौकरियों पर अधिकार जमा रहे हैं। यह सब तब हो रहा है, जब संविधान पूरे देश में निर्बाध रूप से घूमने, रहने और रोजगार पाने आदि का अधिकार देता है।

इस विवाद का दूसरा पहलू भी महत्त्वपूर्ण है, जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जब त्रिभाषा सूत्र को व्यवहार में लाया जा रहा था तो उत्तर भारत में हिंदी और अंग्रेजी के अतिरिक्त लगभग सभी जगहों पर विद्यार्थी तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत पढ़ रहे थे। यह विद्यालयों में आम व्यवहार रूप में अपनाया गया और पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कृत पढ़ी जाती रही। इस बात पर भी गौर करना जरूरी है कि जिन दक्षिण भारतीय लोगों द्वारा हिंदी का विरोध दर्ज कराया जाता है, उनकी भाषा को उत्तर भारतीयों द्वारा कभी सीखने का गंभीर प्रयास नहीं किया गया। यह एक प्रमुख कारण रहा, जिस वजह से हिंदी क्षेत्र ने अपना भरोसा कायम नहीं किया और जब भी हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाए जाने की बहस चली, तो सदैव वहां से तीव्र प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। इसका एक परिणाम यह भी हुआ कि उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीय लोग एक-दूसरे की संस्कृति से कम ही परिचित रहे।

इतिहास में अगर देखा जाए तो आजादी से पूर्व हिंदी से इतर क्षेत्रों के बड़े नेताओं ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में समर्थन दिया। सबसे पहला नाम महात्मा गांधी का है। इसके अलावा बंगाल में केशव चंद्र सेन, दक्षिण में मोदुरी सत्यनारायण, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक और वीर र ने भी हिंदी की ही वकालत की। यही एक भाषा थी, जो सबको जोड़ सकती थी, लेकिन आजादी मिलने के बाद इसे भुला दिया गया और हिंदी की राष्ट्रभाषा की मांग की स्थिति कमजोर होती चली गई। अगर वर्ष 2011 1 को देखें तो 43 फीसद लोगों की प्राथमिक भाषा हिंदी सावरकर की जनगणना की है, लेकिन राष्ट्रभाषा वाला पहलू अब राजनीति से प्रेरित हो गया है। इस बार की जनगणना जो होने वाली है, उसमें इसकी संभावना थोड़ी सकती है, क्योंकि हिंदी क्षेत्रों में जनसंख्या तेजी से बढ़ी है।

यों भाषा का कार्य जोड़ने का है, लेकिन इसे सही दिशा नहीं दी जाए तो यही भाषा तोड़ने का भी कार्य कर सकती है। जैसा अभी हाल के विवादों में देखने को भी मिल रहा है। एक जिम्मेदार नागरिक के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी भाषा के साथ-साथ दूसरे की भाषा का सम्मान करें। सहअस्तित्व का भाव हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। अपनी भाषा से हम अपनी संस्कृति का परिचय प्राप्त करते हैं. हैं, तो दूसरी भाषा से दूसरी संस्कृति का यह क्रम हमें देश की अन्य समृद्ध संस्कृतियों से परिचय का अवसर देता है।

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बढ़ता अमेरिकी आतंक और भारत

दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक होने के कारण अमेरिका लंबे समय से वैश्विक आर्थिक नीतियों पर दबदबा बनाए हुए है। यह दबदबा अब खुलेआम दादागिरी का रूप ले चुका है, खासकर जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मनमाने टैरिफ लगाकर देशों को आर्थिक रूप से झुकाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने के बाद अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ की घोषणा ने इस दादागिरी को और स्पष्ट कर दिया है। यानी कुल मिलाकर 50 फीसदी का टैरिफ – यह न सिर्फ व्यापारिक प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करेगा, बल्कि वैश्विक व्यापार संतुलन पर भी असर डालेगा।

ट्रंप को भारत द्वारा रूस से तेल खरीदने पर आपत्ति है, जबकि विडंबना यह है कि चीन भी यही कर रहा है और अमेरिका स्वयं रूस से यूरेनियम और खाद खरीद रहा है। यानी सिद्धांत और व्यवहार में अमेरिकी नीति दोहरे मानदंडों से भरी है। सवाल यह है कि भारत क्यों अपने हितों को ताक पर रखकर अमेरिकी दबाव में काम करे?

कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भारत पर टैरिफ बढ़ोतरी के एलान के बाद पहली बार एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में प्रतिक्रिया ने भारत के अडिग रुख को और मजबूती से सामने रखा है। उससे भारत का अडिग रवैया परिलक्षित हो रहा है। मोदी ने साफ कह दिया है कि हमारे लिए, हमारे किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। भारत किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। यह वक्तव्य बताता है कि भारत अब वैश्विक दबावों के आगे नतमस्तक नहीं होगा।

यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव (यूएसटीआर) के आंकड़ों के अनुसार भारत-अमेरिका के बीच वार्षिक व्यापार 11 लाख करोड़ रुपये का है। भारत अमेरिका को 7.35 लाख करोड़ रुपये का निर्यात करता है, जिसमें दवाइयाँ, दूरसंचार उपकरण, जेम्स-एंड-ज्वेलरी, पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियरिंग उत्पाद और वस्त्र शामिल हैं। वहीं, अमेरिका से भारत 3.46 लाख करोड़ रुपये का आयात करता है, जिसमें कच्चा तेल, कोयला, हीरे, विमान व अंतरिक्ष यानों के पुर्जे शामिल हैं।

लेकिन यहां चिंता की बात यह है कि चीन, वियतनाम, बांग्लादेश और इंडोनेशिया जैसे देशों पर अमेरिका ने इतना भारी शुल्क नहीं लगाया है, जिससे उनके उत्पाद भारतीय उत्पादों की तुलना में अमेरिकी बाजार में सस्ते पड़ेंगे। फिर भी, मोदी सरकार का रवैया दृढ़ है। साठ के दशक में हम गेहूं, दूध के लिए भी अमरीका पर निर्भर थे लेकिन लगता है ट्रंप ने उन दिनों लिखी गई कोई किताब ताजा मानकर पढ़ ली है। उन्हें आज भी पुराना भारत दिख रहा है, जिसे वह झुकाने की सोच रहे हैं। उन्हें यह समझ में आ जाना चाहिए कि अब भारत पहले वाला भारत नहीं रहा है। वह आत्मनिर्भर एवं विश्व में तेजी से बढ़ती हुई अर्थ व्यवस्था है। भारत का पूरे विश्व में दबदबा बढ़ रहा है। उद्योग जगत भी इस दबाव को एक अवसर के रूप में देख रहा है। उद्योगपति हर्ष गोयनका का कहना है कि अमेरिका निर्यात पर टैरिफ लगा सकता है, लेकिन हमारी संप्रभुता पर नहीं। आनंद महिंद्रा ने तो यह भी कहा कि जैसे 1991 के विदेशी मुद्रा संकट ने उदारीकरण की राह खोली थी, वैसे ही यह टैरिफ संकट भी हमें आत्मनिर्भरता की दिशा में गति दे सकता है। ललित मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ट्रंप को 2023 की उस रिपोर्ट की याद दिलाई है, जो अमेरिका की कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने ही जारी की थी।

गौरतलब है कि गोल्डमैन सैक्स ने इस रिपोर्ट में कहा था कि भारत 2075 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, जो न केवल जापान और जर्मनी, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। रिपोर्ट में अनुमान है कि 2075 तक भारत की जीडीपी 52.5 ट्रिलियन डॉलर होगी, जो चीन के 57 ट्रिलियन डॉलर से कम लेकिन अमेरिका के 51.5 ट्रिलियन डॉलर से अधिक होगी। वर्तमान में, भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और तेजी से आगे बढ़ रही है।

अमेरिका की आर्थिक दादागिरी कोई नई बात नहीं है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद से ही वह वैश्विक आर्थिक नीतियों में अपनी शर्तें थोपता आया है, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। चीन पहले ही उसके दबाव में नहीं आ रहा और अब भारत भी साफ संकेत दे रहा है कि उसकी प्राथमिकता अपने राष्ट्रीय हित हैं। हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत-पाक युद्ध रोकने का श्रेय लेने की अमेरिकी कोशिश को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। यही रुख अब टैरिफ विवाद में भी नजर आ रहा है।

मोदी सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल और इंडिया फर्स्ट जैसी नीतियों के जरिये 2047 तक भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। ऐसे में ट्रंप की टैरिफ राजनीति भारत के आत्मनिर्भरता अभियान को और तेज कर सकती है।

धैर्य और संयम के साथ नेतृत्व करना भारत की ताकत है। रामचरितमानस का वह प्रसंग याद आता है जब विभीषण ने युद्ध के समय श्रीराम से कहा कि रावण के पास सब कुछ है, पर आपके पास कुछ नहीं। तब श्रीराम ने उत्तर दिया कि सबसे बड़ी शक्ति धैर्य, शांति और सहनशीलता है। यही नीति आज भारत के नेतृत्व में झलक रही है जहां ट्रंप अभिमान में हैं, वहीं भारत दृढ़ता और शांति के साथ आगे बढ़ रहा है।

इतिहास ने साबित किया है कि अमेरिका कभी भी भारत का स्थायी मित्र नहीं रहा। ट्रंप की नीतियों का विरोध अमेरिका के भीतर भी हो रहा है। ऐसे में बदलते समीकरण भारत के लिए नए अवसर खोल सकते हैं। ट्रंप भले ही मनमाना रवैया अपनाए हुए हैं पर वह भी फंस रहे हैं। टैरिफ के मुद्दे पर उनका अमरीका में भी विरोध हो रहा है। बदले परिदृश्य मे नए वैश्विक समीकरण बनने की संभावनाएं हैं। ट्रंप का रुख चीन के साथ भारत के संबंधों को बदल सकता है।

पीएम मोदी इस महीने के आखिर में सात सालों के बाद चीन के दौरे पर जा रहे हैं। वह वहां तिआनजिन में 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आयोजित होने वाली शंघाई कोऑपरेशन ऑगेनाईजेशन (एसीओ) समिटम में शामिल होंगे। मोदी का यह चीन दौरा ऐसे समय में होने जा रहा है, जब दोनों देशों के रिश्तों को सुधारने की कोशिशें चल रही हैं। भारत बहुत बड़ा बाजार है, जिसकी चीन को सख्त जरूरत है। भारत मे जब भी स्वदेशी का मुद्दा उठता है तो चीन इसे अपने खिलाफ मानता है। स्वदेशी की अवधारणा का चीनी उत्पादों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में चीन क्यों नहीं चाहेगा कि उसके भारत के साथ संबंध मधुर हों। खासकर, तब जब अमरीका खुद ही भारत से दूरियां बढ़ा रहा है। चीन को भारत के विशाल बाजार की जरूरत है, और अमेरिका के साथ भारत के रिश्तों में दूरी बढ़ने से बीजिंग अपने संबंध सुधारने को उत्सुक होगा।

अमेरिका की आर्थिक दादागिरी भले ही अभी भी जारी हो, पर बदलते वैश्विक परिदृश्य में भारत का आत्मविश्वास, अडिग रुख और दूरदर्शी नेतृत्व इसे न सिर्फ झेलने में सक्षम है, बल्कि इसे अपने विकास की सीढ़ी भी बना सकता है। आने वाले समय में अपने हितों की रक्षा करते हुए दुनिया में अपनी शर्तों पर आगे बढ़ना ही भारत की असली ताकत होगी । अर्थव्यवस्था के शिखर पर पहुंचकर भी भारत वसुधैव कुटुम्बकुम के मार्ग पर चलेगा। सबका कल्याण ही भारत की सोच है। हम तो प्राचीन काल से ही सर्वे भवन्तु सुखिनः ही सोच रखते हैं। दादागिरी हमारा स्वभाव नहीं है। (लेखक विख्यात शिक्षा विद्, विचारक, चिंतक और वक्ता हैं।)

दिल्ली में लैंडफिल गैसें बन रही हैं मुसीबत

प्रमोद भार्गव

दिल्ली की आबोहवा खराब करने में कचरों के ऐसे ठिकाने खतरनाक साबित हो रहे हैं, जिनसे लैंडफिल गैसें हवा और जल स्त्रोतों को एक साथ प्रदूषित करते हैं। दिल्ली समेत समूचे राजनीति क्षेत्र में अनेक लैंडफिल ठिकाने हैं। इसलिए इस पूरे क्षेत्र में कचरे के इन ढेरों से फूटती लैंडफिल नामक षैतानी गैसों से एक बड़ी आबादी का जीना कठिन हो गया है। इन ठिकानों को हटाने और कचरे का वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण करने के लिए विभिंन्न संस्थाएं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण और सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा चुकी हैं, लेकिन अब तक नतीजा ढांक के तीन पांत ही रहा है। अब मौसम विभाग की तर्ज पर लैंडफिल ठिकानों पर अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसी व्यवस्था होगी। इस कचरे से उत्सर्जित होने वाली तीव्र ज्वलनशील मीथेन गैस को चिन्हित करने वाले डिटेक्टर भी लगाए जाएंगे। इन ठिकानों के तापमान पर भी निगरानी रखने के लिए नान कांटेक्ट इंफ्रारेड थर्मामीटर लगाए जाएंगे। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीक्यूएम) ने इन साइटों पर आग लगने की घटनाओं को थामने और इससे होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए 8 सूत्रीय निर्देश भी जारी किए हैं। इन निदेशों का पालन दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान सरकार को एनसीआर नगरों की सभी लैंडफिल साइटों पर इन निर्देशों का पालन करना होगा।

दिल्ली में गाजीपुर, भलस्वा तथा ओखला में लैंडफिल ठिकाने हैं। इनमें रोजाना हजारों टन कचरा डाला जाता है। इसके वैज्ञानिक ढंग से निस्तारण के कोई तकनीकी इंतजाम नहीं हैं। एनजीटी ने एक समिति का गठन कर उससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के कचरे से बिजली पैदा करने की संभावना तलाशने को कहा था, लेकिन दिल्ली सरकार, दिल्ली प्रदूशण नियंत्रण समिति और केंद्रीय प्रदूशण नियंत्रण बोर्ड किसी परिणाम तक नही पहुंच पाए। इन ढेरों में अचानक आग भी लग जाती है, इस कारण समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण जानलेवा साबित होने लगता है। पर्यावरणीय मामलों के प्रमुख वकील गौरव बंसल का कहना है कि ये लैंडफिल कचरों के ठिकाने नहीं हैं। क्योंकि ऐसे ठिकानों के लिए विशेष डिजाइन और कायदे-कानून का प्रावधान है। कचरा डालने से पहले इन मैदानों में मिट्टी, प्लास्टिक, जैव और जैव-चिकित्सा जैसे कचरे को अलग किया जाता है।

जबकि इन ठिकानों पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसलिए ये ठिकाने वेस्ट डंपिंग ग्राउंड बनकर रह गए हैं। दरअसल मीथेन गैस अत्यधिक ज्वलनशील गैस है। अन्य स्त्रोतों के अलावा लैंडफिल ठिकाने पर जमा जैविक कचरे के विघटित होने से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। इस गैस में रंग और गंद नहीं होते है। इस कारण इसके रिसाव का पता नहीं चलता है। माना जाता है कि हवा में 5 से 15 प्रतिशत की सांद्रता से भी आग लग सकती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व अपर निदेशक डॉ एसके त्यागी का कहना है कि मीथेन ग्रीन हाउस गैस है। उपग्रह से इसकी निकली छवि को देखा जा सकता है। इसे ट्रेप कर इसका उपयोग करने पर काम होना चाहिए। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि महानागरों में इस तरह के बड़े कचरे के ढेरों को एकत्रित करने से रोका जाए। इसके लिए कचरे को अलगाने, उसे रिसाइकल करने एवं उससे खाद एवं ईंधन तैयार करने पर विचार होना चाहिए।

दरअसल लैंडफिल गैसें उन स्थलों से उत्सर्जित होती हैं, जहां गड्ढों में षहरी कचरा भर दिया गया हो। इस कचरे में औद्योगिक कचरा भी षमिल हो तो इसमें प्रदूशण की भयानकता और बढ़ जाती है। नए षोधों से पता चला है कि नियम-कानूनों को ताक पर रखकर लापरवाही से तैयार किए भूखंडों पर खड़ी इमारतों में चल रहे सूचना तकनीक के कारोबार में प्रयुक्त चांदी, तांबा और पीतल के कल-पूर्जों की सेहत लैंडफिल गौसों के संपर्क में आकर बिगड़ जाती है। इनका हमला निर्जीव यांत्रिक उपकरणों पर ही नहीं मानव स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल असर डालता है। हमारे देष की महानगर पालिकाएं और भवन-निमार्ता गड्ढो वाली भूमि के समतलीकरण का बड़ा आसान उपाय इस कचरे से खोज लेते हैं। रोजाना घरों से निकलने वाले कचरे और इलेक्ट्रॉनिक कचरे से गड्ढों को पाटने का काम बिना किसी रासायनिक उपचार के कर दिया जाता है। इस मिश्रित कचरे में मौजूद विभिन्न रसायन परस्पर संपर्क में आकर जब पांच-छह साल बाद रासायनिक क्रियाएं करते हैं, तो इसमें से जहरीली लैंडफिल गैसें पैदा होने लगती हैं। इनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड इत्यादी होती हैं। कचरे के सड़ने से बनने वाली इन बदबूदार गैसों को वैज्ञानिकों ने लैंडफिल गैसों के दर्जे में रखकर एक अलग ही श्रेणी बना दी है। दफन कचरे में भीतर ही भीतर जहरीला तरल पदार्थ जमीन की दरारों में रिसता है। यह जमीन के भीतर रहने वाले जीवों के लिए प्राणघातक होता है। भूगर्भ में निरंतर बहते रहने वाले जल-स्त्रोतों में मिलकर यह शुद्ध पानी को जहरीला बना देता है। गंधक के अनेक जीवाणुनाशक यौगिक भूमि में फैलकर उसकी उर्वरा क्षमता को नष्ट कर देते हैं।

आधुनिक जीवन शैली बहुत अधिक कचरा पैदा करती है। इसलिए भारत ही नहीं, दुनिया के ज्यादातर विकसित और विकासशील देश कचरे को ठिकाने लगाने की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर विकसित देशों ने समझदारी बरतते हुए इस कचरे को अपने देशों में ही नष्ट कर देने की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। दरअसल पहले इन देशों में भी इस कचरे को धरती में गड्ढे खोदकर दफना देने की छूट थी। लेकिन जिन-जिन क्षेत्रों में यह कचरा दफनाया गया, उन-उन क्षेत्रों में लैंडफिल गैसों के उत्सर्जन से पर्यावराण बुरी तरह प्रभावित होकर खतरनाक बीमारियों का जनक बन गया। जब ये रोग लाइजाज बीमारियों के रूप में पहचाने जाने लगे तो इन देषों का षासन-प्रषासन जागा और उसने कानून बनाकर औद्योगिक व घरेलू कूड़े-कचरे को अपने देष में दफन करने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए। तब इन देषों ने इस कचरे को ठिकाने लगाने के लिए लाचार देषों की तलाष की और सबसे लाचार देष निकला भारत। दुनिया के 105 से भी ज्यादा देष अपना औद्योगिक कचरा भारत के समुद्री तटवर्ती इलाकों में जहाजों से भेजते हैं। इन देषों में अमेरिका, चीन, ब्राजील, आस्ट्रेलिया, जर्मनी और ब्रिटेन प्रमुख हैं।

नेषनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीयूट के एक षोध पत्र के अनुसार वर्श 1997 से 2005 के बीच भारत में प्लास्टिक कचरे के आयात में 82 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। ये आयात देष में पुनर्षोधन व्यापार को बढ़ावा देने के बहाने किया जाता है। इस क्रम में विचारणीय पहलू यह है कि इस आयातित कचरे में खतरनाक माने जाने वाले ऑगेनी-मरक्यूरिक यौगिक निर्धारित मात्रा से 1500 गुना अधिक पाए गए हैं, जो कैंसर जैसी लाइजाज और भयानक बीमारी को जन्म देते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की मुल्याकांन समीति के अनुसार देष में हर साल 44 लाख टन कचरा पैदा होता है। ऑगेनाईजेशन फॉर कॉरपोरेशन एंड डवलपमेंट ने इस मात्रा को 50 लाख टन बताया है। इसमें से केवल 38.3 प्रतिशत कचरे का ही पुनर्शोधन किया जा सकता है, जबकि 4.3 प्रतिशत कचरे को जलाकर नष्ट किया जा सकता है। लेकिन इस कचरे को औद्योगिक इकाईयों द्वारा ईमानदारी से पूनर्षोधित न किया जाकर ज्यादातर जल स्त्रोतों में धकेल दिया जाता है।

कचरा भण्डारों को नश्ट करने के ऐसे ही फौरी उपायों के चलते एक सर्वे में पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन ने पाया है कि हमारे देष के पेयजल में 750 से 1000 मिलिग्राम प्रति लीटर तक नाइट्रेट पानी में मिला हुआ है और अधिकांष आबादी को बिना किसी रासायनिक उपचार के पानी प्रदाय किया जा रहा है, जो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। एप्को के अनुसार नाइट्रेट बढ़ने का प्रमुख कारण औद्योगिक कचरा, मानव व पषु मल है।

ऐसे ही कारणों से लैंडफिल गैसों का उत्सर्जन बढ़ रहा है। नतीजतन बच्चों में ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी बीमारी फैल रही है। इन गैसों के आंख, गले और नाक में स्थित ष्लेश्मा परत के संपर्क में आने से दमा, सांस, त्वचा और एलर्जी की बिमारियां बढ़ रही हैं। कचरा मैदानों के ऊपर बने भवनों में रहने वाले लोगों में से, खास तौर से महिलाओं में मूत्राषय का कैंसर होने की आषंका बढ़ जाती है। लैंडिफल गैसें इन खतरों को चार गुना बढ़ा देती हैं। यह प्रदूशण गर्भ में पल रहे षिषु को भी प्रभावित करता है।

नियमानुसार कचरा मैदानों में भवन निर्माण का सिलसिला 15 साल बाद होना चाहिए। इस लंबी अवधि में कचरे के सड़ने की प्रक्रिया पूर्ण होकर लैंडफिल गैसों का उत्सर्जन भी समाप्त हो जाता है और जल में घुलनषील तरल पदार्थ का बनना भी बंद हो जाता है। लेकिन प्रकृति की इस नैसर्गिक प्रक्रिया के पूर्ण होने से पहले ही हमारे यहां जमीन के समतल होने के तत्काल बाद ही आलीषान इमारतें खड़ी करने का सिलसिला षुरू कर देते हैं। जिसका नतीजा उस क्षेत्र में रहने वाली आबादी और इलेक्ट्रोनिक उपकरणों को भुगतना होता है।

अब इस औद्योगिक व घरेलू कचरे को नश्ट करने के प्राकृतिक उपाय भी सामने आ रहे है। हालांकि हमारे देष के ग्रामीण अंचलों में घरेलू कचरे व मानव एवं पषु मल-मूत्र को घर के बाहर ही घरों में प्रसंस्करण करके खाद बनाने की परंपरा रही है। इसके चलते कचरा महामारी का रूप धारण कर जानलेवा बीमारियों का पर्याय न बनते हुए खेत की जरूरत के लिए ऐसी खाद में परिवर्तित होता है, जो फसल की उत्पादकता व पौश्टिकता बढ़ाता है। अब एक ऐसा ही अद्वितीय व अनूठा प्रयोग औद्योगिक व घरेलू जहरीले कचरे को नश्ट करने में सामने आया है।

अभी तक हम केंचुओं का इस्तेमाल

गर्मी में भी पसीना कम आना कौन सी बीमारी का लक्षण है? एक्सपर्ट से जानें

गर्मी के मौसम में पसीना आना तो आम बात है. गर्मी में शरीर खुद को ठंडा रखने के लिए पसीना निकालता है. लेकिन अगर तापमान ज्यादा हो और फिर भी आपको पसीना न आए या बहुत कम आए, तो ये सामान्य नहीं है. कई लोग इसे हल्के में ले लेते हैं और सोचते हैं कि पसीना न आना अच्छी बात है क्योंकि इससे कपड़े गीले नहीं होंगे और चिपचिपाहट से बच जाएंगे. लेकिन सच ये है कि शरीर का पसीना न निकालना अंदर ही अंदर एक बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है। जब बाहर 40 डिग्री से ज्यादा तापमान हो और आपका शरीर ठंडा रहने के लिए पसीना ही न निकाले तो गर्मी अंदर ही फंस जाती है. इससे शरीर का टेंपरेचर बढ़ सकता है और हीट स्ट्रोक तक हो सकता है. कई बार ये स्थिति अचानक नहीं बल्कि धीरे-धीरे बनती है।

आपको लगेगा कि पहले जितना पसीना आता था अब उतना नहीं आ रहा है. या फिर शरीर के कुछ हिस्सों में पसीना आ रहा है लेकिन बाकी हिस्सों में बिल्कुल नहीं. ये बदलाव किसी सामान्य थकान या पानी की कमी की वजह से नहीं होते बल्कि इसके पीछे गंभीर वजह छिपी हो सकती है.

गर्मी में कम क्यों आता है पसीना?

दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ अजीत जैन बताते हैं कि पसीना कम आने को मेडिकल भाषा में हाइपोहाइड्रोसिस कहा जाता है।

अगर बिल्कुल भी पसीना न आए तो इसे एन्हाइड्रोसिस (अल्व्रॅंश्ङ्ख-३२) कहा जाता है. ये कोई बीमारी नहीं बल्कि किसी और बीमारी का लक्षण हो सकता है. कई बार ये समस्या गड़बड़ी से होती है. तो कई बार त्वचा या पसीना ग्रंथियों में समस्या के कारण. इस दौरान शरीर अपने तापमान को सही से कंट्रोल नहीं कर पाता और ज्यादा गर्म हो जाता है.

अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों होता है?

इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं. जैसे कुछ लोगों को जन्म से ही पसीना कम आने की समस्या होती है. कुछ मामलों में डायबिटीज, स्किन डिसऑर्डर, नर्व डैमेज या ऑटोइम्यून बीमारियां भी इसका कारण बन सकती हैं. कुछ दवाएं भी पसीना कम कर देती हैं. और अगर आपने कभी रेडिएशन थेरेपी ली है तो उसके बाद भी पसीना आने की क्षमता प्रभावित हो सकती है।

आस्था की भीड़ में खोता इंसान!

सोनम लववंशी

हमारे समय का एक विडंबनापूर्ण दृश्य यह है कि मनुष्य, जिसने अंतरिक्ष की गहराइयों में झांकने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संवाद करने की क्षमता हासिल कर ली है, वह अपने ही पैरों तले कुचलकर भगवान के दर्शन करने के लिए दौड़ रहा है। मध्य प्रदेश के सीहोर स्थित कुबरेश्वर धाम में दो महिलाओं की मौत, कई घायल, यह न तो कोई पहला हादसा है, न आखिरी होने जा रहा है। यह केवल एक घटना नहीं, हमारी सामूहिक चेतना की उस दरार का प्रमाण है जिसमें आस्था, व्यवस्था और विवेक का संतुलन बिखर चुका है और ऐसे में सवाल यही है कि क्या हम आस्था के उस उन्मादी दौर में हैं, जहां किसी की जान की कोई कीमत नहीं? यह सवाल इसलिए भी है, क्योंकि मंदिर या तीर्थस्थल पर जाने से किसी के घर का चिराग बुझ जाए या चूल्हा जलना बंद हो जाए। तो इससे अधिक त्रासदीपूर्ण वेदना कोई दूसरी नहीं हो सकती है। वैसे भी आस्था, जब तक वह आत्मानुशासन और विवेक से जुड़ी रहती है, जीवन को उन्नत करती है। परंतु जब वह भीड़ की बेखबर लय में बहने लगती है, तो वह एक उन्मादी प्रवाह बन जाती है, जिसमें व्यक्ति का व्यक्तित्व, बुद्धि और स्वतंत्र निर्णय शक्ति डूब जाती है। भगदड़ दरअसल भीड़ की शारीरिक टक्कर नहीं है। यह सोच की भी टक्कर है, जहां विज्ञान और व्यवस्था की समझ, परंपरा के अंधविश्वास से हार जाती है।

नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्र्स ब्यूरो के अनुसार, पिछले पच्चीस वर्षों में देश के भीतर 3000 से अधिक लोग मारे गए हैं। इनमें से अधिकांश घटनाएं धार्मिक स्थलों या आयोजनों से जुड़ी हैं। हाथरस में 121 लोग, रतनगढ़ में 115, चामुंडा देवी में 224, नैना देवी में 146, मंधार देवी में 258, दिल्ली स्टेशन 18, ये सब हमें एक ही बात कह रहे हैं कि भगवान भीड़ में नहीं मिलते, विवेक में मिलते हैं। लेकिन इक्कीसवीं सदी का मानव है कि इसे समझने को तैयार नहीं और इन सभी घटनाओं का पैटर्न लगभग एक जैसा रहा। क्षमता से कई गुना अधिक भीड़, अपर्याप्त निकासी मार्ग, आपातकालीन प्रबंधन का अभाव और अफवाह की एक चिंगारी, जो पलों में मृत्यु की लपट बन जाती है। यह भीड़ का मनोविज्ञान है। जिसमें व्यक्ति अपनी सोच खो देता है और एक अज्ञात भय या लालसा में, दूसरों को धकेलते हुए आगे बढ़ने लगता है। यह वह क्षण होता है जब मनुष्य, जो तर्कशील होने का दावा तो करता है, फिर अपने सबसे आदिम स्वभाव में लौट आता है कि पहले मैं। धार्मिक आयोजनों में यह प्रवृत्ति और गहरी हो जाती है, क्योंकि उसमें पुण्य और मोक्ष जैसे अदृश्य पुरस्कार जुड़े होते हैं, जो लोगों को यह विश्वास दिलाते हैं कि समय गंवाना पाप है, और रुकना हानि।

सबसे बड़ा दोष इस सोच का है कि ह्लभगवान सब देख रहे हैं, वे बचा लेंगे ह्व यह विचार न केवल बौद्धिक आलस्य है, बल्कि जिम्मेदारी से भागने का भी एक साधन है। जीवन रक्षा का विज्ञान कहता है कि किसी भी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्पष्ट प्रवेश और निकास मार्ग, भीड़ की गणना का वैज्ञानिक आकलन, आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था, और प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की अनिवार्यता। पर हमारे यहां धार्मिक आयोजनों में यह सब श्रद्धा के आगे गौण मान लिया जाता है। आयोजक इसे भगवान की कृपा के भरोसे छोड़ देते हैं, और प्रशासन इसे भावनात्मक मामला समझकर कठोर कदम उठाने से बचता है।

अमेरिका में ट्रंप के करीबी चार्ली किर्क की हत्या, हिल गया देश, व्हाइट हाउस में झंडा आधा झुकाया गया

एजेंसी

वाशिंगटन (अमेरिका)। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप के करीबी और दक्षिणपंथी युवा कार्यकर्ता चार्ली किर्क की हत्या से सारा देश हिल गया। दलगत भावना से ऊपर उठकर शोक में डूबे देश में फिर से बंदूक हिंसा के खिलाफ आवाज भी उठनी शुरू हो गई है। कुछ लोग इसे राजनीतिक हत्या बता रहे हैं। चार्ली किर्क को दोपहर यूटा वैली विश्वविद्यालय में टर्निंग पॉइंट यूएसए कार्यक्रम के दौरान गोली मारी गई। लहूलुहान चार्ली को बचाया नही जा सका। अस्पताल पहुंचने से पहले रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका के हर-छोटे बड़े सूचना संचार माध्यम में चार्ली की मौत को महत्व दिया गया है। द न्यूयॉर्क टाइम्स और एनबीसी न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, चार्ली की मौत की सूचना मिलते ही राष्ट्रपति ट्रंप अवाक रह गए। कुछ देरतक उनके आसपास सन्नाटा पसरा रहा। पूरी पड़ताल के बाद उन्होंने दोपहर बाद ट्रुथ सोशल पर उनके निधन की घोषणा की। ट्रंप ने किर्क को महान बताते हुए लिखा, अमेरिका में युवाओं के दिल को चार्ली से बेहतर कोई नहीं समझ सकता था। सभी उन्हें प्यार करते थे। उन्होंने कहा कि वह चार्ली को कभी भुला नहीं पाएंगे।

नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रमुख हो सकती हैं पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की!

काठमांडू (नेपाल)। नेपाल में सोशल मीडिया पर सरकार के प्रतिबंध लगाने के खिलाफ हुए बवाल और खूनखराबा के बीच प्रधानमंत्री केपी ओली (खड्ग प्रसाद ओली) शर्मा इस्तीफा दे चुके हैं। इसके बाद उनके किसी स्थान पर चले जाने से आई राजनीतिक शून्यता को भरने की कवायद तेज हो गई है। आंदोलन का नेतृत्व करने वाले जेन जी समूह में शामिल युवाओं ने कई नामों पर विचार किया है। नेताओं के भ्रष्टाचार और राजनीति में फैले भाई-भतीजावाद से आजिज गोरखाओं के धैर्य का बांध एक तरह से टूट चुका है। जन विद्रोह की लपटों में अठतालीस घंटे से अधिक झुलसे हिमालयी देश में फैली अराजकता को रोकने के लिए नेपाली सेना को मंगलवार शाम कमान संभालनी पड़ी। पटरी पर लौट रहे देश को संभालने के लिए फिलहाल अंतरिम सरकार के चयन पर विचार-विमर्श हो रहा है । अंतरिम सरकार की प्रमुख उच्चतम न्यायालय की पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की हो सकती हैं। उनके नाम पर सहमति बनती दिख रही है।

जापान के कई हिस्सों में भारी बारिश, भूस्खलन को लेकर चेतावनी जारी

टोक्यो । जापान की मौसम एजेंसी ने गुरुवार को कहा कि देश के कई हिस्सों में वायुमंडलीय स्थितियां बहुत अस्थिर हैं, और पश्चिमी जापान के शकोकू क्षेत्र में सुबह ही मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी (जेएमए) के अनुसार, तड़के नागासाकी और कुमामोटो के दक्षिण-पश्चिमी प्रान्तों में भारी वर्षा हुई। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, जेएमए ने बताया कि गुरुवार सुबह शिकोकू, होकुरिकु और तोहोकू क्षेत्रों में काले घने बादल छा गए, इसके बाद झमाझम बरसात हुई। उन्होंने आगे कहा कि आने वाले घंटों में बरसात होती रहेगी।मौसम अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि क्यूशू से तोहोकू तक के क्षेत्रों में देर शाम तक वायुमंडलीय परिस्थितियां अत्यधिक अस्थिर रहेंगी, और पश्चिमी और पूर्वी जापान में स्थानीय स्तर पर भारी बारिश हो सकती है। ठंडी हवा के द्रव्यमान और लो प्रेशर ट्रफ के कारण देर शाम तक होक्काइडो के कुछ हिस्सों में भी मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान है। जेएमए ने कहा कि शुक्रवार सुबह तक 24 घंटों की अवधि के दौरान दक्षिणी क्यूशू में 180 मिलीमीटर, कांटो-कोशिन क्षेत्र में 120 मिलीमीटर और टोकाई क्षेत्र में 100 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है।

नेपाल में नई पीढ़ी के नेतृत्व की मांग, 'हमें भी पीएम मोदी जैसा नेता चाहिए'

काठमांडू। नेपाल में राजनीतिक उथल-पुथल और जन आंदोलन के बीच अंतरिम सरकार पर विचार-विमर्श होने लगा है। इसमें अहम यह है कि नेपाल में लोगों के बीच भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जैसे चेहरे की मांग उठ रही है। कई नागरिकों ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे नेतृत्व की तुलना करते हुए नेपाल में भी समान दृष्टिकोण वाले नेता की जरूरत पर जोर दिया है। काठमांडू के एक स्थानीय निवासी ने कहा, हमें पीएम मोदी जैसे प्रधानमंत्री की जरूरत है, जो देश के लिए सोचता हो और उसे प्रगति की ओर ले जाए। हम पीएम मोदी का समर्थन करते हैं और नेपाल में भी ऐसा ही नेता चाहते हैं। यह बयान नेपाल में चल रहे जन आंदोलन और पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद आए राजनीतिक संकट के बीच सामने आया है। काठमांडू के एक स्थानीय युवक ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, अभी जो चाहा था, वही हो रहा है और अच्छा हो रहा है। बुरा वक्त जा चुका है। यह यूथ के लिए बड़ी बात है कि 35 घंटे में सरकार बदल गई। हमें अब कुछ दिन के लिए अंतरिम प्रधानमंत्री चाहिए। हमें यह भी सोचना पड़ेगा कि कुछ दिनों बाद चुनाव हों और इसके बाद प्रधानमंत्री चुना जाए। उन्होंने यह भी कहा, हमें प्रधानमंत्री मोदी जैसे प्रमुख की जरूरत है, जो देश के बारे में सोचे और उसकी प्रगति में योगदान दे। हम प्रधानमंत्री मोदी का समर्थन करते हैं और नेपाल में भी प्रधानमंत्री के रूप में ऐसा ही नेता चाहते हैं। हालांकि, नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम पर कुछ स्थानीय लोगों ने आपत्ति जताई।

अपदस्थ प्रधानमंत्री ओली की पार्टी ने आंदोलन और हिंसक घटनाओं पर चुप्पी तोड़ी

एजेंसी

नई दिल्ली। नेपाल के अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी) ने आंदोलन और हिंसक घटनाओं पर चुप्पी तोड़ी है। पार्टी के महासचिव शंकर पोखरेल ने जिम्मेदार लोगों की पहचान की मांग करते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई का आह्वान किया है। उन्होंने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को व्यापक नुकसान पहुंचाए जाने की निंदा की। पार्टी ने इस आंदोलन में मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करके घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। पार्टी के केंद्रीय सचिवालय की ओर से महासचिव शंकर पोखरेल ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि पार्टी ने जिम्मेदार लोगों की पहचान की मांग करते हुए कड़ी कानूनी कार्रवाई का आह्वान किया। उन्होंने औपचारिक रूप से हाल ही में विनाशकारी विरोध

प्रदर्शनों पर गहरी चिंता व्यक्त की है, जिसने सोमवार और मंगलवार को देश को हिलाकर रख दिया था। पोखरेल ने यह स्वीकार करते हुए कहा कि विरोध प्रदर्शन सोशल मीडिया प्रतिबंधों, भ्रष्टाचार विरोधी मांगों और सुशासन की मांग पर केंद्रित थे। यूएमएल ने सार्वजनिक और निजी संपत्ति को व्यापक नुकसान की निंदा करके मृतकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।पार्टी ने मंगलवार को आगजनी, लूटपाट और हिंसा की राष्ट्रव्यापी घटनाओं को दुखद बताया। उन्होंने कहा कि संसद, राष्ट्रपति कार्यालय, सिंघा दरबार, सुप्रीम कोर्ट, संवैधानिक एजेंसियों, हवाई अड्डों, पुलिस स्टेशनों, निजी संपत्ति और दुर्लभ रिकॉर्ड सहित सरकारी इमारतों को नष्ट कर दिया गया, जिससे दशकों तक देश नहीं उबर पाएगा। पार्टी ने अशांति के दौरान नेपाल पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल और नेपाली सेना सहित सुरक्षा एजेंसियों की देरी और अपर्याप्त प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाया। पोखरेल ने पार्टी कैडरों को एकजुट रहने, उच्च मनोबल बनाए रखने, नष्ट कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों की सफाई में सहायता करने, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने और प्रभावित नागरिकों को सहायता देने का निर्देश दिया। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद यूएमएल ने राजनीतिक संकट के संवैधानिक और लोकतांत्रिक समाधान की आवश्यकता पर जोर डाला। पार्टी ने राष्ट्रपति से भ्रष्टाचार विरोधी उपायों, भाई-भतीजावाद को समाप्त करने, सुशासन और रोजगार सृजन सहित युवाओं की चिंताओं को दूर करने के लिए सार्थक बातचीत शुरू करने का आग्रह किया।

पिछले माह ईरान और पाकिस्तान से 2,38,700 अफगान वापस लौटे

एजेंसी

काबुल (अफगानिस्तान)। अफगानिस्तान शरणार्थी समाधान आयोग ने कहा कि पिछले महीने ईरान और पाकिस्तान से 2,38,700 अफगान वापस लौटे हैं। आयोग के प्रवक्ता अहमदुल्लाह वसीक ने पिछले दिनों जारी बयान में कहा, अफगानों की जबरन वापसी जारी है और सिर्फ एक महीने में 2,38,700 लोग वापस आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि सरकार उनके पुनर्वास का इंतजाम कर रही है।द काबुल टाइम्स की रिपोर्ट में प्रवक्ता के हवाले से बताया गया कि कई लोग अब इस्लामिक अमीरात से आश्रय, रोजगार, बच्चों की शिक्षा और खोई हुई संपत्ति के लिए सहायता सहित अपनी तत्काल जरूरतों को पूरा करने का आग्रह कर रहे हैं। आयोग ने आश्वासन दिया कि प्रमुख क्षेत्रों में वापस लौटने वालों के लिए सेवाओं और सहायता में सुधार के प्रयास जारी हैं। पड़ोसी देशों, विशेष रूप से ईरान और पाकिस्तान से अफगान प्रवासियों और शरणार्थियों की बड़े

पैमाने पर वापसी के बाद से इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़ग़ानिस्तान ने उनकी तत्काल और दीर्घकालिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कई उपाय किए हैं।

मेक्सिको में गैस टैंकर में विस्फोट, तीन की मौत, 70 घायल

एजेंसी

मेक्सिको सिटी । मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी के इज्टापलासा में हाइवे अंडरपास में एक गैस टैंकर में विस्फोट के बाद आग लग गई। इस हादसे में कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कम से कम 70 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, शहर की मेयर क्लारा ब्रुगाडा ने सोशल मीडिया पर आग से झुलसे लोगों की सूची जारी की। ब्रुगाडा ने पत्रकारों को बताया था कि कम से कम 19 लोगों की हालत गंभीर है। मौके पर पहुंचीं ब्रुगाडा ने कहा, यह दुखद है। अभियोजक कार्यालय ने जांच शुरू कर दी है।

मेक्सिको सिटी के गृहमंत्री पाब्लो वाजक्वेज़ कैमाचो के अनुसार, टैंकर चालक को अस्पताल ले जाया गया। वह अभी भी जीवित है, लेकिन उसकी हालत गंभीर है। बताया गया है कि विस्फोट के बाद लगी आग ने आसपास के वाहनों को लपटों में घेर लिया। इससे इज्टापलापा में अफरा-

तफरी मच गई। इज्टापलापा में मजदूरों की संख्या अधिक है। यह राजधानी का सबसे अधिक आबादी वाला नगर है, जहां 18 लाख लोग रहते हैं।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, कई लोग जले हुए कपड़ों के साथ दर्द से कराहते हुए इधर-उधर भटकते रहे। दोपहर तक दमकलकर्मियों ने आग बुझा दी थी, लेकिन गैस टैंकर से रिसाव को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे। राजधानी के अग्निशमन विभाग की प्रवक्ता जूडिथ रोड्रिग्ज वर्गास के अनुसार, टैंकर में अभी भी लगभग 20,000 लीटर (लगभग 5,300 गैलन) ईंधन होने का अनुमान है।

उज्बेकिस्तान ने अफगानिस्तान का अनुरोध स्वीकार किया, 57 सैन्य हेलीकॉप्टर सौंपेगा

एजेंसी

काबुल (अफगानिस्तान)। इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान के प्रवक्ता ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि उज्बेकिस्तान कथित तौर पर अफगानिस्तान को 57 सैन्य हेलीकॉप्टर वापस करने पर सहमत हो गया है। इन सैन्य हेलीकॉप्टर को अगस्त 2021 में पूर्व गणराज्य के पतन के दौरान देश से बाहर भेज दिया गया था।

द काबुल टाइम्स अखबार के अनुसार, मुजाहिद ने कहा कि इन हेलीकॉप्टर को गणराज्य के पतन के समय भागे हुए अफगान सैन्य कर्मियों ने ले लिया था। यह कुछ वर्षों से उज्बेकिस्तान की धरती पर ही हैं। उन्होंने कहा कि इन हेलीकॉप्टरों के भविष्य को लेकर काबुल और ताशकंद के बीच चुपचाप बातचीत चल रही थी और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी राष्ट्रीय संपत्तियों को पुनः प्राप्त करने के व्यापक प्रयासों के तहत लगातार इनकी वापसी का अनुरोध कर रही थी। प्रवक्ता ने आशा व्यक्त की, निकट भविष्य में

57 सैन्य हेलीकॉप्टरों का हस्तांतरण होने की उम्मीद है। यह अफगानिस्तान की हवाई क्षमताओं को बहाल करने और दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। रक्षा विशेषज्ञों के अनुसार, हेलीकॉप्टरों की वापसी को एक प्रतीकात्मक और रणनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। यह मध्य एशिया में शांति और संपर्क बनाए रखने की उज्बेकिस्तान की इच्छा को दर्शाता है।

नासा की तकनीकी प्रणालियों तक प्रवासी चीनी नागरिकों की पहुँच पर लगी रोक

एजेंसी

वाशिंगटन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चीन के प्रवासी पेशेवरों पर डेटा प्रणालियों और आंतरिक बैठकों जैसी अपनी सुविधाओं तक पहुँच को प्रतिबंधित कर दिया है। नासा की प्रवक्ता बेथानी स्टीवंस ने इस आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि यह कदम चीन के संस्थानों के साथ औपचारिक सहयोग पर लंबे समय से लगे प्रतिबंधों के अलावा स्नातक छात्रों, विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों और ठेकेदारों जैसे उन व्यक्तियों को भी लक्षित करता है जिन्होंने पहले अमेरिकी अंतरिक्ष परियोजनाओं में योगदान दिया था। स्टीवंस ने कहा कि प्रतिबंधों का उद्देश्य हमारे काम की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।इस बीच ब्लूमबर्ग के अनुसार पांच सितंबर को चीनी नागरिकों की नासा प्रणालियों और बैठकों तक भौतिक और डिजिटल पहुँच समाप्त हो गई है। यह दोनो देशो बीच बढ़ती प्रतिस्परधा रेखांकित करता है क्योंकि अमेरिका

और चीन मानवयुक्त चंद्र मिशनों की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिये नासा का लक्ष्य 2027 और बीजिंग का लक्ष्य 2030 है। उधर नासा के कार्यवाहक प्रशासक सीन डफी ने चीन के अंतरिक्ष कार्यक्रम को एक सैन्य अभियान बताते हुए कहा है कि अंतरिक्ष की दौड़ में चीन को हराना बेहद महत्वपूर्ण है । डफी ने चेताया है कि अमेरिका अंतरिक्ष को नहीं छोड़ सकता।

गौरतलब है कि यह निर्णय चंद्र अन्वेषण में अमेरिका को आगे रखने के लिए अमेरिका के दोनों राजनीतिक दलों के बढ़ते दबाव के साथ आया है। सीनेटर टेड क्रूज़ और मारिया कैंटवेल ने आरोप लगाया है कि चंद्रमा पर स्थायी रूप से पैर जमाने की चीन की महत्वाकांक्षाएँ उच्च रणनीतिक दांव लगाती हैं । उन्होंने इस प्रतिस्पर्धा को प्रतीकात्मक प्रतिष्ठा से कहीं अधिक के रूप में प्रस्तुत किया। इस बीच नीति विशेषज्ञों ने इस बाबत अतिक्रमण के जोखिमों की चेतावनी दी। यूनियन ऑफ कंसर्न्ड साइंटिस्ट्स के ग्रेगरी कुलाकी ने कहा कि पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष की भीड़भाड़ के लिए सहयोग की आवश्यकता है जबकि क्रिंसी इंस्टीट्यूट के डेनिस साइमन ने प्रतिबंध की आलोचना करते हुए इसे चीन-विरोधी भ्रम बताते हुए कहा कि यह कदम प्रतिभाओं को बाहर करके अमेरिकी वैज्ञानिक नवान्वेषण को कमजोर कर सकता है। गौरतलब है कि ये प्रतिबंध अमेरिकी विधि विभाग के चीनी पहल संबंधी विवादास्पद कार्यक्रम को पुनर्जीवित करने के प्रयासों के साथ मेल खाते हैं । वह एक ऐसा कार्यक्रम था जिसे नस्लीय भेदभाव के आरोपों के बाद 2022 में रोक दिया गया था। इस आदेश को कुछ सीनेटरो ने नासा तक चीन की पहुँच पर रोक लगाने वाला कदम बताया है जबकि कुछ डेमोक्रेट् सीनेटरों ने चेतावनी दी है कि यह उपाय नागरिक अधिकारों और वैज्ञानिक आदान-प्रदान के लिए एक झटका है।

श्रीलंका एयरलाइंस ने नेपाल के लिए सेवा फिर शुरू की

एजेंसी

कोलंबो। नेपाल में हिंसा के दौरान बंद रहे काठमांडू अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को फिर से खोलने के बाद श्रीलंकाई एयरलाइंस ने आज नेपाल के लिए अपनी सेवा दोबारा शुरू कर दी। उड़ान संख्या यूएल-181 भंडारनायके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से सुबह 8:15 बजे काठमांडू के लिए रवाना हुई। काठमांडू से वापसी उड़ान के शाम 4: 40 बजे पहुंचने की उम्मीद है।

डेली मिरर अखबार की रिपोर्ट में श्रीलंकाई एयरलाइंस के संचार प्रबंधक (कॉर्पोरेट) दीपल परेरा के हवाले से बताया गया कि नेपाल में चल रहे संघर्ष के कारण हवाई अड्डे के बंद होने के बाद एयरलाइंस ने 10 सितंबर को नेपाल के लिए अपनी सेवा निलंबित कर दी थी। भंडारनायके अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि एयरलाइंस ने कल काठमांडू जाने की उम्मीद में आए 35 यात्रियों को आवास और होटल की सुविधा प्रदान की। श्रीलंकाई एयरलाइंस मौजूदा समय में कोलंबो और काठमांडू के बीच उड़ानें संचालित करने वाली एकमात्र एयरलाइन है। परेरा ने बताया कि यह सेवा सप्ताह में रविवार, सोमवार, बुधवार और गुरुवार को संचालित होगी।

पोलैंड का एकतरफा ऐलान, बेलारूस से लगी सीमा करेगा सील

एजेंसी

वारसॉ/मिन्स्क। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने कहा है कि उनका देश गुरुवार आधी रात से बेलारूस के साथ अपनी सीमा पूरी तरह से बंद कर देगा। एक सरकारी बैठक से पहले टस्क ने कहा, ÷राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से, हम बेलारूस के साथ सीमा, जिसमें रेलवे क्रॉसिंग भी शामिल हैं, गुरुवार आधी रात से शुक्रवार तक बंद कर देंगे। समाचार एजेंसी ने पोलिश प्रेस एजेंसी के हवाले से बताया कि यह बंद सभी क्रॉसिंगों, खासकर रेलवे क्रॉसिंगों पर लागू होगा। बेलारूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार, , बेलारूस ने रूस-बेलारूस सैन्य अभ्यास जापद-2025 के दौरान लिए गए पोलैंड के फैसले का विरोध किया है। बेलारूसी पक्ष ने पोलैंड के प्रभारी राजदूत क्रिज्सटॉफ ओजाना को मिन्स्क में तलब किया है और मौखिक विरोध दर्ज कराया है बेलारूसी विदेश मंत्रालय ने कहा कि

पोलैंड के इस एकतरफा कदम से पूरी यूरोपीय संघ-बेलारूस सीमा प्रभावित होने की आशंका है, जिससे लोगों और सामानों की आवाजाही बाधित होगी। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस घोषणा के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी सैनिक पोलैंड में तैनात रहेंगे और उनकी संख्या में और वृद्धि हो सकती है। ट्रंप ने 3 सितंबर को पोलैंड के नए राष्ट्रपति करोल नवरोकी के साथ व्हाइट हाउस में हुई बैठक में ÷पोलैंड की सुरक्षा में मदद÷ करने का वादा किया था। जब पत्रकारों से पूछा गया कि क्या वह नाटो के पूर्वी हिस्से में अग्रिम पंक्ति के देश में अमेरिकी सैनिकों को रखने की योजना बना रहे हैं, तो ट्रंप ने कहा, ÷अगर वे चाहेंगे तो हम वहां और सैनिक तैनात करेंगे। नवरोकी ने ट्रंप को उनके देश के साथ निरंतर सहयोग की प्रतिबद्धता के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा, ये संबंध मेरे लिए, पोलैंड के लिए और हमारे नागरिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। पोलिश प्रेस एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त की शुरुआत में, अमेरिकी विदेश विभाग ने पोलैंड को एफ-35 लड़ाकू विमानों के रखरखाव, रसद और समर्थन से संबंधित एक पैकेज की संभावित बिक्री को मंजूरी दी थी।

पेंटागन की रक्षा सुरक्षा सहयोग एजेंसी (डीएससीए) का हवाला देते हुए, रिपोर्टों में कहा गया है कि जनरल इलेक्ट्रिक एयरोस्पेस इस अनुबंध के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा, जिसकी अनुमानित लागत 1.85 बिलियन डॉलर है। डीएससीए ने कहा कि यह बिक्री ÷नाटो सहयोगी की सुरक्षा बढ़ाकर संयुक्त राज्य अमेरिका की विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों का समर्थन करेगी, जो यूरोप में राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता के लिए एक महत्वपूर्ण शक्ति बनी हुई है।

खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना ने टीटीपी के 19 आतंकी मार गिराए

एजेंसी

इस्लामाबाद। सुरक्षा बलों ने खैबर पख्तूनख्वा में तीन अलग-अलग अभियानों में 19 आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना को नौ और 10 सितंबर को तीन अलग-अलग मुठभेड़ों में यह सफलता मिली। सभी मारे गए आतंकी प्रतिबंधित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीपी) के हैं।

डान अखबार की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान सेना की मीडिया शाखा इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (आईएसपीआर) ने गुरुवार को बताया कि खैबर पख्तूनख्वा के मोहमंद जिले में आतंकवादियों के बारे में एक खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाया गया। भीषण गोलीबारी में 14 आतंकी मारे गए। इसके अलावा उत्तरी वजीरिस्तान जिले के दत्ता खेल

इलाके में चार और आतंकवादियों को ढेर कर दिया। बन्नू जिले में हुई एक अन्य मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया।उल्लेखनीय है कि पिछले हफ्ते बन्नू जिले में संघीय कांस्टेबुलरी (एफसी) मुख्यालय पर हुए हमले में सुरक्षा बलों के छह जवान मारे गए थे। अगस्त में, सुरक्षा बलों ने बलोचिस्तान में चार दिवसीय अभियान के दौरान 50 आतंकवादियों को मार गिराया था।

काठमांडू मेयर बालेन शाह ने अंतरिम सरकार का किया समर्थन

एजेंसी

काठमांडू। रैपर से राजनेता बने काठमांडू के मेयर बालेन शाह ने नेपाल में अंतरिम सरकार के नेतृत्व वाले शासन में बदलाव की तैयारी के बीच बुधवार को शांति और धैर्य बनाए रखने की सार्वजनिक अपील की है। जेनरेशन जेड और नेपाली जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए देश के एक अभूतपूर्व राजनीतिक दौर में प्रवेश को स्वीकार किया। उन्होंने नए चुनावों की देखरेख के लिए एक कार्यवाहक प्रशासन के गठन का समर्थन व्यक्त किया। बालेन शाह ने पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की को अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त करने के प्रस्ताव का समर्थन किया और इसे युवाओं द्वारा एक परिपक्व और विचारशील निर्णय बताया। उन्होंने लिखा, आपकी जागरूकता, विवेक और ए ता गहरे सम्मान के पात्र हैं। उन्होंने राजनीतिक आकांक्षियों को नेतृत्व की भूमिकाएं निभाने में जल्दबाजी न करने की चेतावनी देते हुए कहा कि उनकी ऊर्जा और प्रतिबद्धता दीर्घकालिक बदलाव के लिए आवश्यक है, न कि अस्थायी व्यवस्था के लिए। नेपाल के राष्ट्रपति से सीधी अपील में शाह ने संसद को तत्काल भंग करने और एक अंतरिम सरकार की औपचारिक स्थापना का आह्वान किया।

नेपाल में अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने के लिए कुलमन घिसिंग का नाम प्रस्तावित

एजेंसी

काठमांडू। नेपाल में राजनीतिक संकट के बीच जेन जी के एक समूह ने कुलमान घीसिंग को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाने का प्रस्ताव रखा है। नेपाल में फंसे भारतीय पर्यटकों को ले जाने के लिए इंडिगो एयरलाइंस का चार्टर्ड विमान काठमांडू पहुंच गया है। इस बीच सेना प्रमुख जनरल अशोक राज ने राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल को मौजूदा हालात की जानकारी दी है। सेना मुख्यालय के बाहर झड़प में आंदोलनकारियों के दो गुट आपस में भिड़ गए। नेपाल में नई सरकार को लेकर गुरुवार को सेना मुख्यालय में आर्मी चीफ जनरल अशोक राज के नेतृत्व में अहम बैठक हुई, जिसमें जेन-जी के सात प्रतिनिधि भी शामिल हुए। अपना प्रतिनिधि चुनने के मुद्दे पर सेना मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे युवाओं में फूट पड़ गई, जिसके बाद दो गुट आपस में ही भिड़ गए। बैठक में मौजूद सुशीला कार्की और दुर्गा प्रसाई के नाम पर सहमति न बनने पर लंबी वार्ता के बाद प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए अब कुलमन घिसिंग का नाम आगे रखा है। कुलमान घीसिंग के पास प्रशासनिक अनुभव है और उन्होंने ऊर्जा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है।

सेना प्रमुख ने राष्ट्रपति को स्थिति से अवगत कराया उधर, सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिग्देल ने राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल से बात कर उनको सभी स्थिति से अवगत कराया है। उन्होंने राजनीतिक और संवैधानिक प्रयासों के बारे में जानकारी दी है। प्रदर्शनकारियों ने अंतरिम प्रधानमंत्री के लिए सुशीला कार्की के नाम का विरोध इसलिए किया है, क्योंकि उनके पति पर विमान अपहरण का आरोप है और उन्होंने इस मामले में दो साल मुंबई की जेल में बिताए हैं। नेपाल की प्रथम महिला प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्की की नियुक्ति अपदस्थ प्रधानमंत्री केपी ओली के संवैधानिक परिषद् के अध्यक्ष रहते की गई थी। नेपाल की संसद में एक बार सुशीला कार्की के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव भी लाया गया था, जिसके बाद कुछ दिनों तक उन्हें अपने पद से निलंबित रहना पड़ा। बाद में कोर्ट ने उनके निलंबन को खारिज करते हुए उन्हें दोबारा प्रधान न्यायाधीश के रूप में काम करने के लिए फैसला सुनाया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दाहाल प्रचंड ने एक बयान में संसद विघटन नहीं करने और संविधान के दायरे में समाधान ढूंढने की अपील करते हुए कहा कि यह आंदोलन संविधान और संसद के विरोध में नहीं था। इसलिए संसद भंग करने का परिणाम ठीक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और गणतंत्र पर कोई समझौता नहीं हो सकता है। युवाओं के इस आंदोलन के बाद लोकतंत्र और गणतंत्र को और मजबूत करना पहली जिम्मेदारी है। प्रचंड ने कहा कि युवाओं की मांग संसद विघटन की मांग नहीं, बल्कि संविधान में आवश्यक बदलाव किये जाने की है। इसलिए संवैधानिक और राजनीतिक संकट के समाधान के लिए सभी पक्षों के बीच सहमति आवश्यक है।

नेपाल में फंसे भारतीय पर्यटकों को ले जाने के लिए इंडिगो एयरलाइंस का चार्टर्ड विमान काठमांडू पहुंच गया है। इंडिगो एयरलाइन्स के दो विमान काठमांडू आने हैं, जिसमें एक विमान लैंड कर चुका है और दूसरा लैंड करने वाला है। नेपाल में हुए व्यापक उपद्रव से होटल इंडस्ट्री बुरी तरह प्रभावित हुई है और कारोबार में 50 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि सोमवार और मंगलवार को आयोजित जेन-जी विरोध प्रदर्शनों के दौरान अब तक 34 लोगों की मौत हो चुकी है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देशभर के अस्पतालों में 1,338 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 949 लोगों को पहले ही छुट्टी दे दी जा चुकी है।

डॉलर की तुलना में रुपये में मामूली तेजी, यूरो और ब्रिटिश पौंड की तुलना में रहा शानदार दर्शन

एजेंसी
नई दिल्ली। विदेशी संस्थागत निवेशकों के घरेलू शेयर बाजार में फ्रेश इनवेस्टमेंट करने और अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने की उम्मीद में रुपये ने एक बार फिर मजबूती दिखाई। आज के कारोबार में रुपये ने डॉलर के मुकाबले मामूली तेजी हासिल की, लेकिन दूसरी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं की तुलना में रुपये का शानदार प्रदर्शन रहा। भारतीय मुद्रा आज सिर्फ 2 पैसे उछल कर 88.10 रुपये (अनंतिम) के स्तर पर बंद हुई। इससे पहले पिछले कारोबारी दिन मंगलवार को भारतीय मुद्रा 88.12 रुपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुई थी। रुपये ने आज के कारोबार की शुरुआत मामूली कमजोरी के साथ की थी। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में भारतीय मुद्रा ने आज सुबह डॉलर के मुकाबले सिर्फ 1 पैसे की गिरावट के साथ 88.13 रुपये के स्तर से कारोबार की शुरुआत की थी। आज का कारोबार शुरू होने के बाद रुपया फिसल कर 88.19 के स्तर तक पहुंचा। इसके बाद रुपये को विदेशी संस्थागत निवेशकों की स्टॉक मार्केट में की गई खरीदारी से सहारा मिलन लगा।

स्टॉक मार्केट में ऑप्टिवैल्यू टेक की शानदार शुरुआत, फायदे में आईपीओ निवेशक

नई दिल्ली। टेक कंसल्टिंग कंपनी ऑप्टिवैल्यू टेक कंसल्टिंग के शेयरों ने आज स्टॉक मार्केट में जोरदार एंट्री करके अपने आईपीओ निवेशकों को खुश कर दिया। आईपीओ के तहत कंपनी के शेयर 84 रुपये के भाव पर जारी किए गए थे। आज एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर इसकी लिस्टिंग 23.33 प्रतिशत प्रीमियम के साथ 103.60 रुपये के स्तर पर हुई। लिस्टिंग के बाद लिवाली के सपोर्ट से ये शेयर उछल कर 107.55 रुपये के स्तर तक पहुंचा। हालांकि इसके बाद मुनाफा वसूली शुरू हो जाने के कारण ये शेयर 101.80 रुपये के स्तर तक गिर कर बंद हुआ। मुनाफा वसूली होने के बावजूद आज पहले दिन के कारोबार में कंपनी के आईपीओ निवेशकों को 21.19 प्रतिशत का मुनाफा हो गया। ऑप्टिवैल्यू टेक कंसल्टिंग का 126 करोड़ रुपये का आईपीओ 2 से 4 सितंबर के बीच सब्सक्रिप्शन के लिए खुला था। इस आईपीओ को निवेशकों की ओर से शानदार रिस्पॉन्स मिला था। इसे कारण ये ओवरऑल 64.45 गुना सब्सक्राइब हुआ था। इनमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबी) के लिए रिजर्व पोर्शन 49.27 गुना सब्सक्राइब हुआ था। वहीं नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (एनआईआई) के लिए रिजर्व पोर्शन में 118.82 गुना सब्सक्रिप्शन आया था।

लगातार तीसरे दिन मजबूती के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, निवेशकों को 1 दिन में 2.65 लाख करोड़ का मुनाफा

नई दिल्ली। मजबूत ग्लोबल संकेतों और अमेरिका के साथ ट्रेड डील को लेकर बढ़ी उम्मीद की वजह से घरेलू शेयर बाजार में आज उत्साह का माहौल बना रहा। आज के कारोबार के दौरान दिन के पहले सत्र में लगातार खरीदारी होती रही। हालांकि दूसरे सत्र में मुनाफा वसूली शुरू हो जाने के कारण सेंसेक्स और निफ्टी दोनों सूचकांकों की चाल में गिरावट भी आई। पूरे दिन के कारोबार के बाद सेंसेक्स 0.40 प्रतिशत और निफ्टी 0.42 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुए। आज दिनभर के कारोबार के दौरान आईटी सेक्टर में लगातार दूसरे दिन जमकर खरीदारी होती रही। इसके साथ ही बैंकिंग, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज और रियल्टी सेक्टर के शेयरों में भी लगातार खरीदारी होती रही। इसके अलावा एफएमसीजी, फार्मास्यूटिकल, एनर्जी, कैपिटल गुड्स, मेटल, ऑयल एंड गैस और टेक इंडेक्स भी मजबूती के साथ बंद हुए। दूसरी ओर, ऑटोमोबाइल और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेक्टर के शेयरों में लगातार बिकवाली का दबाव बना रहा। ब्रॉडर मार्केट में भी आज लगातार खरीदारी होती रही, जिसके कारण बीएसई का मिडकैप इंडेक्स 0.84 प्रतिशत की मजबूती के साथ बंद हुआ। इसी तरह स्मॉलकैप इंडेक्स ने 0.72 प्रतिशत की तेजी के साथ आज के कारोबार का अंत किया। आज शेयर बाजार में आई मजबूती के कारण स्टॉक मार्केट के निवेशकों की संपत्ति में ढाई लाख करोड़ रुपये से अधिक की बढ़ोतरी हो गई।

ब्रदर इंटरनेशनल इंडिया ने भारतीय बाजार में 6 इंक टैंक प्रिंटर किए लॉन्च

नई दिल्ली। ब्रदर इंटरनेशनल ने भारतीय बाजार में छह उच्च दक्षता वाले इंक टैंक प्रिंटरों की एक नई श्रृंखला लॉन्च की है। कंपनी ने इन प्रिंटरों को घरेलू उपयोगकर्ताओं, कार्यालय पेशेवरों और छोटे व्यवसायों की उभरती मुद्रण जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया है। ब्रदर इंटरनेशनल इंडिया के उच्च दक्षता वाले इन छह इंक टैंक प्रिंटरों की शुरुआती कीमत 13,990 रुपये से लेकर 35,590 रुपये तक है। ब्रदर इंटरनेशनल इंडिया के निदेशक सलीम निशो और प्रबंध निदेशक आलोक निगम ने नई दिल्?ली में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में बताया कि कंपनी ने क्षमता, उपयोग में आसानी और कनेक्टिविटी पर ध्यान केंद्रित करते हुए उच्च दक्षता वाले इंक टैंक प्रिंटरों का निर्माण किया है।ये प्रिंटर नवीनतम लाइनअप भारतीय बाजार के लिए स्मार्ट, विश्वसनीय और लागत प्रभावी प्रिंटिंग समाधान प्रदान करने के लिए ब्रदर इंटरनेशनल इंडिया की प्रतिबद्धता को मजबूत करता है। इसके अलावा हाल के वर्षों में दूरस्थ शिक्षा उपकरणों की बढ़ती मांग और छोटे व्यवसायों के डिजिटलीकरण के कारण, बहुमुखी और कॉम्पैक्ट प्रिंटिंग उपकरणों की जरूरतें अनिवार्य हो गई है। ब्रदर इंटरनेशनल इंडिया के प्रिंटर की रेंज के अभियान की थीम अनुभव को रंगीन बनाएं।

अगस्त में 3 लाख वाहन स्क्रैप, बीएस-7 मानदंडों के साथ वैश्विक स्टैंडर्ड अपनाएंगे: गडकरी

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति देश की अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिए वरदान साबित हो रही है। अगस्त 2025 तक 3 लाख वाहन स्क्रैप हो चुके हैं, जिनमें से 1 लाख 41 हजार सरकारी वाहन थे, जबकि देश में 97.4 लाख वाहनों को स्क्रैप किया जा सकता है। गडकरी ने नई दिल्ली में सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआईएएम) के 65वें वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से स्क्रैपिंग के बाद नई गाड़ियां खरीदने वाले लोगों को जीएसटी में राहत देने का अनुरोध किया है। वर्तमान में मासिक 16,830 वाहन स्क्रैप हो रहे हैं और निजी क्षेत्र ने इस क्षेत्र में 2,700 करोड़ रुपये का निवेश किया है। भारत प्रतिवर्ष 27 लाख टन स्टील आयात करता है, जो स्क्रैपिंग से प्राप्त किया जा सकता है। इसी तरह एल्यूमीनियम का आयात भी कम हो सकता है। स्क्रैपिंग से अब तक 3.67 लाख टन स्टील निकाला गया है, जो कुल जरूरत का मात्र 6 प्रतिशत है। यदि स्क्रैप धातुओं से नई गाड़ियां बनाई जाएं तो केंद्र और राज्य सरकारों को 40 हजार करोड़ रुपये का राजस्व लाभ होगा, साथ ही ऑटोमोबाइल कंपनियों को भी लागत में भारी कमी का फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि भारत ने बीएस-4 से बीएस-6 उत्सर्जन मानदंडों पर पहुंच गया है, जो सभी पक्षों के समन्वय का परिणाम है। अब बीएस-7 मानदंडों और कॉरपोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी (कैफे) को अपनाने के लिए वैश्विक मानकों, विशेष रूप से यूरोपीय स्टैंडर्ड्स के साथ तालमेल बनाए रखा जाएगा।

वायु प्रदूषण को देश की सबसे बड़ी समस्या बताते हुए उन्होंने कहा कि परिवहन क्षेत्र कुल प्रदूषण का 40 प्रतिशत योगदान देता है। स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ रहा है। गडकरी ने एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि माल परिवहन का 81 प्रतिशत सड़कों से, मात्र 1 प्रतिशत रेल से और 17 प्रतिशत अन्य माध्यमों से होता है। सड़कों का विस्तार तेजी से हो रहा है। एक्सप्रेसवे निर्माण कार्य चल रहा है।

डिजिटल उद्यम असिस्ट पंजीकरण के लिए फोनपे ने सिडबी से हाथ मिलाया

एजेंसी
नई दिल्ली। वित्तीय प्रौद्योगिकी (फिनटेक) क्षेत्र की कंपनी फोनपे ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन पर केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता सूक्ष्म उद्यमों और व्यापारियों को सशक्त बनाने के लिए उद्यम असिस्ट मंच (यूएपी) के जरिए संपूर्ण डिजिटल समाधान प्रदान करने के लिए किया गया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म के जरिए उद्यमों को पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय और सिडबी का यह ऐतिहासिक कदम है, जिससे कई उद्यमियों को लाभ होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इससे उद्यमियों की मदद होगी। हम बहुत कम समय में गरीबी मिटाने की दिशा में ऐसे लोगों के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। इस सहयोग का उद्देश्य भारत भर के असंगठित सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को डिजिटल प्रथम उद्यम असिस्ट पंजीकरण प्रदान करके संगठित बनाना है, जिससे उन्हें सरकारी योजनाओं, ऋण सुविधाओं और व्यापक डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र सहित लाभों तक पहुंच प्राप्त हो सके। इस अवसर पर फोनपे क्रेडिट सर्विसेज के मुख?य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) हेमंत गाला ने कहा कि आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन है। उन?होंने कहा कि हमने जो किया है वह यह है कि एमएसएमई मंत्रालय ने उद्यम असिस्ट पोर्टल बनाया था। इस पोर्टल ने व्यापारियों को डिजिटल रूप से खुद को ऑनबोर्ड करने और उनके लिए एक व्यावसायिक प्रमाणपत्र बनाने में सक्षम बनाया। सिडबी के साथ मिलकर हमने एक ऐसी प्रक्रिया बनाई है, जिसके तहत हम फोनपे बिजनेस ऐप के माध्यम से व्यापारियों को डिजिटल रूप से ऑनबोर्ड करते हैं और उन्हें एक व्यावसायिक प्रमाणपत्र देते हैं।

ऑटोमोबाइल सेक्टर के बाजार विस्तार और सप्लाई चेन को मजबूत करने में केंद्र सरकार करेगी मदद

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार का ध्यान ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास को बढ़ावा देने, रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने और बाजार के आकार व पहुंच का विस्तार करने पर है। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशंस (फाडा) के सातवें ऑटो रिटेल कॉन्क्लेव और चौथे फाइनेंस एंड इंश्योरेंस समिट के उद्घाटन के दौरान केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि ऑटोमोबाइल रिटेल सेक्टर कंज्यूमर और इंडस्ट्री के बीच एक इंटरफेस है, जो मार्केटिंग की नैतिकता, अच्छी गुणवत्ता वाली सेवा, उचित वित्तपोषण और बीमा शर्तों और बेहतर रजिस्ट्रेशन प्रक्रियाओं के लिए जिम्मेदार है। केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि यह सेक्टर ग्राहकों और ऑटोमोबाइल कंपनियों के बीच एक सेतु का काम करता है और कंपनियों की विश्वसनीयता डीलर के काम करने और उपभोक्ताओं को सेवा प्रदान करने के तरीके पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि ऑटोमोबाइल के अधिक किफायती होने के साथ जीएसटी सुधार का लाभ 22 सितंबर से उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री गोयल ने बिक्री के बाद की सेवा, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और ग्राहकों के लिए निरंतर समर्थन के महत्व पर भी जोर दिया।

उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले देखे गए हैं, जिनमें कंपनियां भारत में काम तो शुरू करती हैं लेकिन कुछ समय बाद ही काम को बंद कर चली जाती हैं। ऐसे में ऐसी कंपनियों के उत्पादों को खरीदने वाले ग्राहकों के लिए चुनौतियां पैदा होती हैं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा, ऐसे मामलों में ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने की जिम्मेदारी डीलर्स पर आ जाती है। व्यवधान को रोकने और खरीदारों की सुरक्षा के लिए उन्होंन एक फ्रेमवर्क या चार्टर बनाने के सुझाव दिया, जिसके तहत भारत में काम करने वाली सभी कंपनियों को परिचालन बंद करने की अनुमति मिलने से पहले एक निश्चित अवधि तक स्थानीय उपस्थिति बनाए रखने और बिक्री के बाद सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध होना होगा। उन्होंने कहा कि इससे ग्राहकों की निराशा दूर होगी साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर की विश्वसनीयता बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि भारत कई विकसित देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौतों पर बातचीत कर रहा है और वैश्विक कंपनियों से निवेश आकर्षित कर रहा है। उन्होंने घरेलू उद्योग और निर्माताओं का समर्थन करते कहा कि प्रतिस्पर्धा निष्पक्ष होनी चाहिए, क्योंकि प्रतिस्पर्धा से दक्षता, उत्पाद की गुणवत्ता और उपभोक्ता की पसंद में सुधार होता है। उन्होंने कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में वृद्धि तब होगी जब ग्लोबल कंपनियां अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में टेस्ट कर सकेंगी, जिससे एक बड़े निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

एचएमएसआई 350 सीसी के मॉडल के दाम 18,800 रुपये तक घटाएगी, नई कीमतें 22 सितंबर से होगीं प्रभावी

एजेंसी
नई दिल्ली। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एचएमएसआई) ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को देने का ऐलान किया है। कंपनी ने इसके तहत अपने 350 सीसी तक के मॉडल की कीमतें 18,800 रुपये तक घटाने का फैसला किया है। संशोधित कीमतें 22 सितंबर से प्रभावी होंगी।

कंपनी ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि वह अपने उत्पाद पोर्टफोलियो में हाल ही में जीएसटी दर में की गई कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देगी। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया ने इसके तहत 350 सीसी तक के अपने दोपहिया वाहनों की कीमत में कटौती की है, जिससे इनकी कीमतें 18,800 रुपये तक कम हो गई हैं। इसमें स्कूटर और मोटरसाइकिल दोनों शामिल होंगे। एचएमएसआई के निदेशक बिक्री एवं विपणन योगेश माथुर ने कहा कि दोपहिया वाहनों और कलपुर्जों पर जीएसटी में कमी एक समयोचित और दूरदर्शी कदम है, जिससे वाहन अधिक किफायती बनेंगे और समग्र पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा। उन?होंने कहा कि कंपनी ने यह कदम जीएसटी परिषद की ओर से हाल ही में दोपहिया वाहनों पर टैक?स की दर को 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी करने के निर्णय के बाद उठाया गया है। योगेश माथुर ने कहा कि कंपनी ने यह कदम ग्राहकों को लाभ पहुंचाने और बाजार को मजबूत करने के लिए उठाया है।

भारत में एप्पल के मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने से रोजगार के नए अवसर होंगे पैदा, टैक्स चोरी में आएगी कमी : रिपोर्ट

एजेंसी
नई दिल्ली। एक्सपर्ट्स का कहना है कि टेक कंपनी एप्पल आईफोन 17 रेंज को भारत में मैन्युफैक्चर करेगी, कंपनी के इस कदम से सप्लाई चेन की दक्षता में वृद्धि होगी, टैक्स लीकेज घटेगा और साथ ही देश की प्रीमियम डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थिति मजबूत होगी। ग्रांट थॉर्नटन भारत के अनुसार, एप्पल के विस्तारित फुटप्रिंट से समर्थित मेक इन इंडिया पहल से निर्यात को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के अवसरों में वृद्धि होगी। साथ ही, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग पावरहाउस के रूप में भारत की विश्वसनीयता बढ़ने की उम्मीद है। एप्पल, फॉक्सकॉन और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से तमिलनाडु और कर्नाटक में प्रोडक्शन शिफ्ट कर बेसिक कस्टम ड्यूटी से बच जाता है। अन्यथा कंपनी को आयायित फुली एसेंबल डिवाइस पर यह शुल्क देना पड़ेगा। ग्रांट थॉर्नटन

भारत में टैक्स प्लानिंग और ऑप्टिमाइजेशन-पार्टनर कृष्ण अरोड़ा ने कहा कि लोकल असेंबली कंपनी को अमेरिका में संभावित टैरिफ वृद्धि से भी बचाती है। अमेरिका द्वारा भारत पर उच्च टैरिफ लगाए जाने के बाद, देश के कुछ निर्यातों पर अब 50 प्रतिशत तक के शुल्क लग रहे हैं, हालांकि स्मार्टफोन पर अभी इस तरह के शुल्क लागू नहीं है। एप्पल के इस कदम से भारत की उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत भी लाभ हुआ है। यह योजना पिछले पांच वर्षों से भारत में निर्मित फोन की बिक्री में वृद्धि पर 4-6 प्रतिशत नकद प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। अरोड़ा ने आगे कहा, हालांकि, कंपनी के इस निर्णय से भारत में उपभोक्ताओं के लिए कीमतें तुरंत कम नहीं होंगी। उन्होंने आगे कहा कि इससे एप्पल के कॉन्ट्रैक्ट निर्माताओं को वित्त वर्ष 2024-25 में आईफोन निर्यात में 10 बिलियन डॉलर से अधिक का आंकड़ा पार करने में मदद मिली है। इसी के साथ 2025 की पहली छमाही में निर्यात सालाना आधार प 53 प्रतिशत बढ़कर 23.9 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया है। 2025 की पहली छमाही में भारत में असेंबल किए गए 78 प्रतिशत आईफोन अमेरिका भेजे गए, जो एक वर्ष पहले 53 प्रतिशत था। तमिलनाडु सरकार ने पूंजीगत सब्सिडी, फास्ट-ट्रैक्ड एनवायरमेंटल क्लीयरेंस और डेडिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्क की पेशकश की है, जबकि कर्नाटक ने रियायती दरों पर जमीन, बिजली दरों में छूट और स्किल डेवलपमेंट ग्रांट की पेशकश की है।

यूरो प्रतीक सेल्स का आईपीओ 16 सितंबर को खुलेगा, प्राइस बैंड 235-247 रुपये प्रति शेयर

एजेंसी
मुंबई। यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) 16 सितंबर को खुलेगा। निवेशक इसमें निवेश करने के लिए 18 सिंतबर तक बोली लगा सकते हैं। कंपनी ने इसके लिए मूल?य का दायरा (प्राइस बैंड) 235-247 रुपये प्रति शेयर तय किया है। यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड ने एक बयान में बताया कि उसका आईपीओ 16 सितंबर को अभिदान के लिए खुलकर गुरुवार, 18 सितंबर 2025 को बंद होगा। कंपनी ने 1 रुपये अंकित मूल्य वाले इस आईपीओ के लिए मूल्य का दायरा 235-247 रुपये प्रति शेयर तय किया है। निवेशक इसमें न्यूनतम 60 इक्विटी शेयरों और उसके बाद 60 इक्विटी शेयरों के गुणकों में बोली लगा सकते हैं। यह आईपीओ पूरी तरह से प्रमोटर और प्रमोटर समूह के शेयरधारकों द्वारा 451 करोड़ रुपये तक बिक्री पेशकश (ओएफएस) है। इस ऑफर में कर्मचारी आरक्षण वाले हिस्से में आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों के लिए आरक्षण भी शामिल है। यूरो प्रतीक सेल्स लिमिटेड की स्थापना 19 जनवरी, 2010 को

हुई थी। मुंबई मुख्यालय वाली यह कंपनी एक परिसंपत्ति-रहित व्यवसाय मॉडल पर काम करती है। कंपनी का मुख्य ध्यान उत्पाद डिजाइन और विकास पर है। एक्सिस कैपिटल लिमिटेड और डीएएम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड इसके बुक-रनिंग लीड मैनेजर हैं, एमयूएफजी इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) इस प्रस्ताव का रजिस्ट्रार है।

खाद्य वस्तुओं की कीमतों में गिरावट के कारण महंगाई अगस्त में 2 प्रतिशत रहने का अनुमान : रिपोर्ट

एजेंसी
नई दिल्ली। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित महंगाई दर या खुदरा महंगाई दर अगस्त में 2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। यह जानकारी गुरुवार को जारी हुई बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट में दी गई।

सरकारी बैंक की ओर से कहा गया कि महंगाई के निचले स्तरों पर रहने की वजह आवश्यक वस्तु सूचकांक (ईसीआई) में कमजोरी बने रहना है। बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार, ईसीआई लगातार चार महीनों से अपस्फीति क्षेत्र में है। इसमें अगस्त में सालाना आधार पर -1 प्रतिशत की और सितंबर के पहले 9 दिनों में -0.9 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि सब्जियों और दालों की अच्छी पैदावार के कारण खाद्य वस्तुओं की

कीमतें नियंत्रण में रहेंगी। सितंबर में टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है।

इसके अलावा वैश्विक स्तर पर भी खाद्य और ऊर्जा की कीमतें नियंत्रण में बनी हुई हैं।बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा, सरकार द्वारा अधिकांश एफएमसीजी और टिकाऊ वस्तुओं सहित अन्य पर जीएसटी दरों को कम करने का वर्तमान कदम महंगाई के मोर्चे पर राहत की बात है। हमारा अनुमान है कि सीपीआई पर इसका समग्र प्रभाव 55-75 आधार अंक रहेगा। सूचकांक में शामिल 20 में से 10 वस्तुओं में अपस्फीति देखी गई, जिसमें सबसे तेज गति प्याज और आलू में देखी गई।

रिपोर्ट में कहा गया है कि प्याज की खुदरा कीमतों में सालाना आधार पर सबसे अधिक -37.5 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। यह जनवरी 2021 के बाद सबसे तेज गिरावट थी। आलू के लिए भी, वर्तमान मूल्य 44 महीनों के निचले स्तर पर है। दालों में, अधिकांश उप-घटकों में लगातार अपस्फीति देखी जा रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा कि सबसे ज्यादा गिरावट तुअर/अरहर में देखी जा रही है, जिसमें अगस्त में -29 प्रतिशत की गिरावट आई है। दालों की अन्य श्रेणियां, जिनमें उल्लेखनीय गिरावट देखी गई हैं, उसमें उड़द (-8.9 प्रतिशत), मूंग (-5.2 प्रतिशत) और मसूर (-1.4 प्रतिशत) शामिल हैं। मुद्रास्फीति में गिरावट बेहतर उत्पादन से समर्थित है। वास्तव में, चालू खरीफ सीजन में, दालों के बुवाई क्षेत्र में सुधार हुआ है। अनाजों में, चावल की खुदरा कीमत धीमी गति से कम हुई है।

सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में मामूली तेजी, चांदी की घटी चमक

एजेंसी
नई दिल्ली। घरेलू सर्राफा बाजार में सोना आज मामूली बढ़त के साथ कारोबार करता नजर आ रहा है। जबकि चांदी के भाव में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई है। कीमत में आई तेजी के कारण देश के ज्यादातर सर्राफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज 1,10,520 रुपये से लेकर 1,10,670 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। दूसरी ओर, 22 कैरेट सोना आज 1,01,310 रुपये से लेकर 1,01,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बिक रहा है। चांदी के भाव में कमजोरी के कारण ये चमकीली धातु दिल्ली सर्राफा बाजार में आज 1,29,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर बिक रही है।

दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,10,670 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 1,01,460 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। वहीं, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 24 कैरेट सोना 1,10,520 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,01,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। इसी तरह अहमदाबाद में 24 कैरेट सोने की रिटेल कीमत 1,10,570 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोने की कीमत 1,01,360 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई है। इन प्रमुख शहरों के अलावा चेन्नई में 24 कैरेट सोना आज 1,10,520 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर और 22 कैरेट सोना 1,01,310 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बिक रहा है। कोलकाता में भी 24 कैरेट सोना 1,10,520 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,01,310 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर कारोबार कर रहा है। लखनऊ के सर्राफा बाजार में 24 कैरेट सोना आज 1,10,670 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर और 22 कैरेट सोना 1,01,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। पटना में 24 कैरेट सोने की कीमत 1,10,570 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर है, जबकि 22 कैरेट सोना 1,01,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है। जयपुर में 24 कैरेट सोना 1,10,670 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट सोना 1,01,460 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बिक रहा है।

ईडी का 346 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में दिल्ली-एनसीआर सहित नौ ठिकानों पर छापा

एजेंसी
नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने दिल्ली-एनसीआर, तमिलनाडु और कर्नाटक में नौ ठिकानों पर छापेमारी की है। यह छापेमारी हरियाणा स्थित एक बिजली क्षेत्र की कंपनी और उसके प्रमोटरों द्वारा कथित तौर पर 346 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी के गुरुग्राम क्षेत्रीय कार्यालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पांच परिसरों, चेन्नई में तीन और बेंगलुरु में एक ठिकानों में छापेमारी की है। यह जांच गुरुग्राम स्थित हाइथ्रो पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के खिलाफ है, जो परिसमापन (लिक्विडेशन) के दौर से गुजर रही है। इसके निदेशकों अमूल गबरानी और अजय कुमार बिश्नोई के अलावा कुछ अन्य लोगों के खिलाफ भी ईडी की जांच जारी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी का यह मामला धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत दर्ज फरवरी 2025 की सीबीआई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें प्रमोटरों पर आरोप है कि उन्होंने ऋण राशि को अपनी कुछ संबद्ध संस्थाओं को हस्तांतरित कर दिया, जिससे बैंकों को नुकसान हुआ।

मध्य प्रदेश को मिले 14,600 करोड़ के निवेश प्रस्ताव, 16 हजार रोजगार होंगे सृजित

एजेंसी
भोपाल। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में कोलकाता के एक होटल में निवेश संभावनाओं पर आयोजित इंटरैक्टिव सेशन में 14,600 करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। इनमें रुईया ग्रुप के पवन कुमार रूईया ने 4200 करोड़, विक्रम सोलर के ज्ञानेश चौधरी ने नवकरणीय ऊर्जा के 10,150 करोड़ रुपये, इसेन बायोग्रीन प्रा.लि./आयुरवृद्धि के यशवर्धन अग्रवाल ने फूड प्रोसेसिंग के लिए 150 करोड़, अजंता ग्रुप के विपुल कंसाल ने फुट वियर क्षेत्र में 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया। इन निवेश प्रस्तावों से प्रदेश में 16 हजार 900 लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे।यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इंटरैक्टिव सेशन को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में उत्पादित आर्गेनिक कॉटन की मांग अनेक देशों में है। प्रदेश टेक्सटाइल का हब बनने की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में सात पीएम मित्रा पार्क स्वीकृत किये। उसमें से पहले पीएम मित्रा पार्क का भूमि-पूजन करने प्रधानमंत्री मोदी 17 सितम्बर को धार जिले में आ रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने उद्योगपतियों का आह्वान किया कि वे मध्य प्रदेश आएं, राज्य सरकार निवेशकों को पीएम मित्रा पार्क में हर संभव सहायता और सुविधा उपलब्ध करवायेगी। धार का पीएम मित्रा पार्क भारत के औद्योगिक विकास की यात्रा में महत्वपूर्ण आयाम जोड़ेगा।

मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों के इंटरैक्टिव सेशन में मध्य प्रदेश को निवेश और औद्योगिक विकास के लिए सबसे भरोसेमंद और अवसरों से भरा राज्य बताया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, देश के मध्य में स्थित होने के कारण उत्तम कनेक्टिविटी, विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचा और औद्योगिक शांति इसे उद्योगपतियों के लिए आदर्श निवेश स्थल बनाते हैं। उन्होंने कहा कि यह पार्क राज्य के टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर को वैश्विक मानकों तक पहुंचाने के साथ रोजगार और आर्थिक विकास में नए आयाम खोलेगा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की शुद्ध और ऑर्गेनिक कॉटन उत्पादन क्षमता इसे टेक्सटाइल निवेश के लिए विशेष बनाती है। पीएम मित्रा पार्क के माध्यम से राज्य में उत्पादन और प्रोसेसिंग के उच्च मानक स्थापित होंगे, जिससे निवेशकों को लाभ के साथ रोजगार के अवसर भी सुनिश्चित होंगे। उन्होंने उद्योगपतियों को भरोसा दिलाया कि राज्य में निवेश स्थिर, पारदर्शी और सुरक्षित वातावरण में किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों का आहवान किया कि आइये हम संकल्प लें कि स्वदेशी अपनायेंगे, हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेंगे और प्रधानमंत्री श्री मोदी के मेक इन इंडिया और विकसित भारत के संकल्प को पूरी शक्ति के साथ साकार करेंगे। मुख्यमंत्री ने कोलकाता की समृद्ध सांस्कृतिक और बौद्धिक परंपरा का सम्मान करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाषचंद्र बोस और रवींद्रनाथ टैगोर जैसे महापुरुषों ने देश को नई दिशा दी। उन्होंने कहा कि यह प्रेरक इतिहास और बौद्धिक परंपरा उद्योग जगत के लिए प्रेरक है और मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास और निवेश के दृष्टिकोण से साथ जुड़ती है। मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि कोलकाता जैसे ऐतिहासिक और बौद्धिक केंद्र से संवाद करना राज्य में निवेश के लिए उत्साह और नई ऊर्जा प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि राज्य में विकसित औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक हब और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर निवेशकों को मजबूत प्रतिस्पर्धी लाभ देते हैं। सड़क, रेल और हवाई नेटवर्क के माध्यम से पूरे देश में उत्पाद और सेवाओं की आपूर्ति सरल और त्वरित रूप से की जा सकती है।

'रागिनी एमएमएस 3' से बाहर हुई

नोरा फतेही

अब इस एक्ट्रेस पर टिकी एकता कपूर की नजर

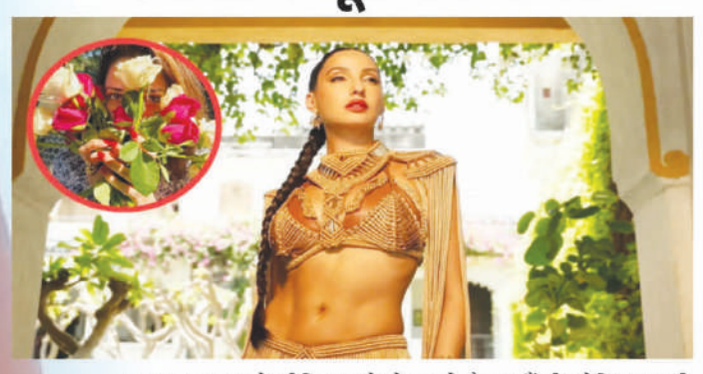

एकता कपूर अपने सीरियल को लेकर तो फेमस हैं ही, लेकिन उनकी फिल्मों को भी लोग काफी पसंद करते हैं. उन्हीं फिल्मों में से फेमस फ्रेंचाइजी की अगली किस्त का भी इंतजार हर किसी को है. हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं, वो है 'रागिनी एमएमएस 3'. एक पुराने इंटरव्यू में एकता ने इस फिल्म को लेकर बताया था कि इस पर काम चल रहा है, जिसके बाद सामने आया था कि नोरा फतेही फिल्म में लीड रोल प्ले करेंगी. हालांकि, अब बताया जा रहा है कि वो फिल्म से बाहर हो चुकी हैं और उनकी जगह दूसरी एक्ट्रेस का भी नाम सामने आ चुका है.'रागिनी एमएमएस' साल 2011 में रिलीज हुई थी, जिसमें कैनाज मोतीवाला और राजकुमार राव अहम किरदार में थे. इसके 3 साल बाद फिल्म का सेकंड पार्ट रिलीज हुआ, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था. फिल्म में सनी लियोनी, साहिल प्रेम, संध्या मृदुल जैसे कलाकार शामिल थे. अब इतने वक्त के बाद इस फिल्म का तीसरा पार्ट चर्चा में आ गया है, जिसमें पहले नोरा फतेही दिखने वाली थीं, लेकिन अब बताया जा रहा है कि नोरा की जगह मेकर्स ने तमन्ना भाटिया का नाम चुन लिया है.

किस वजह से छोड़ी फिल्म

फिल्म से जुड़े एक सोर्स ने बताया कि डेट की परेशानी की वजह से नोरा फिल्म का हिस्सा नहीं हैं. हालांकि, उन्होंने ये बताया कि फिल्म के मेकर्स के लिए लीड रोल के लिए पहली पसंद नोरा ही थीं, लेकिन उनकी इंटरनेशनल कमिटमेंट की वजह से उन्हें ये प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ रहा है. हालांकि, फिल्म के मेकर्स की तरफ से अभी तक इसके किसी भी कास्ट या कहानी के बारे में कोई भी जानकारी ऑफिशियल तौर पर सामने नहीं आई थी.

सक्सेसफुल हॉरर फ्रेंचाइजी

रागिनी एमएमएस के बारे में बात करें, तो ये एक सक्सेसफुल हॉरर फ्रेंचाइजी है. हालांकि, फिल्म के तीसरे पार्ट को लेकर लोगों में काफी एक्साइटमेंट है, साथ ही जब से फिल्म में तमन्ना भाटिया का नाम जुड़ा है, तब से लोगों की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है. फिल्म के मेकर्स इसके तीसरे पार्ट के बारे में कई सारी बातें अभी सीक्रेट रख रहे हैं, जिसके चलते अभी तक फिल्म की कास्ट की ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी गई है.

दीपिका पादुकोण ने सेलिब्रेट किया बेटी दुआ का पहला जन्मदिन, खुद बनाया स्पेशल चॉकलेट केक

बेटी के लिए दीपिका ने बनाया केक

जब से दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह माता-पिता बने हैं, तभी से वह काम के अलावा अपना सारा वक्त अपनी बेटी दुआ के साथ गुजारना पसंद करते हैं. दुआ के पैदा होने के बाद दीपिका की पूरी दुनिया ही बदल चुकी हैं. बेटी की परवरिश के चलते अभी तक दीपिका ने अपनी अगली फिल्म की शूटिंग भी शुरू नहीं की है. हालांकि उनके पास कई प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं. इसी बीच एक्ट्रेस ने अपनी बेटी दुआ के पहले जन्मदिन को खास बनाने के लिए केक बनाया है.

दरअसल दीपिका ने दुआ के बर्थडे पर एक स्पेशल पोस्ट शेयर कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. 8 सितंबर 2024 को दुआ का जन्म हुआ था. दुआ के पहले जन्मदिन को खास बनाने के लिए दीपिका ने खुद अपने हाथों से केक बनाया और उसकी तस्वीर अपने सभी फैन्स के साथ शेयर भी की. एक्ट्रेस ने फोटो के साथ कैप्शन में लिखा, मेरी प्रेम भाषा? बेटी के पहले जन्मदिन के लिए केक बेक किया है.

जब बेटी के नाम का किया था खुलासा

इससे पहले एक फोटो कैप्शन में दीपिका ने खुलासा किया था कि दुआ नाम, जिसका अर्थ है प्रार्थना, चुनने में उन्हें जन्म के लगभग दो महीने लग गए – एक विचारशील निर्णय जिसके बारे में वह कहती हैं कि यह हमारे लिए उनके मतलब का एक सुंदर सारांश जैसा लगा. हालांकि फैन्स दीपिका और रणवीर की बेटी दुआ की झलक देखने के लिए बेकरार हैं. लेकिन कपल अपनी बेटी की प्राइवेसी का पूरा ध्यान रख रहा है. वह दुआ को फिलहाल कैमरों से दूर रखना चाहते हैं.

दुआ की वीडियो हो गई थी लीक

दीपिका ने हाल ही में कहा था कि वे फिलहाल बेटी का चेहरा नहीं दिखाएंगे और सुर्खियों से दूर एक शांत बचपन को प्रायोरिटी देंगे.

हालांकि बीते दिनों दुआ की एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी. जिसमें दीपिका की गोद में एक छोटी बच्ची नजर आ रही थी. कपल ने बिना उनकी सहमति के बेटी की वीडियो वायरल होने पर नाराजगी जाहिर की थी. दीपिका के फैन्स ने भी उनका सपोर्ट किया था.

मनीषा कोइराला से झरना बज्राचार्य तक, इन 7 नेपाली कलाकारों ने बॉलीवुड में जमाई धाक

Genz प्रोटेस्ट के बीच नेपाल में तख्तापलट हो चुका है. इस वक्त ये देश पूरी दुनिया में चर्चा में बना हुआ है. इस देश के कई टैलेंटेड कलाकारों ने दुनियाभर में अपना नाम रोशन किया है. भारतीय सिनेमा, खासकर बॉलीवुड, हमेशा से नेपाली कलाकारों के लिए एक बड़ा मंच रहा है. आइए नजर डालते हैं उन 7 नेपाली एक्टर्स पर, जिन्होंने बॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से जादू बिखेरा और दिखाया कि कैसे कला सीमाओं को पार कर जाती है.

मनीषा कोइराला

नेपाल के राजघराने से ताल्लुक रखने वाली मनीषा कोइराला ने 90 के दशक में बॉलीवुड पर राज किया. 'बॉम्बे', 'दिल से', 'खामोशी' जैसी फिल्मों से उन्होंने अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाया. आज भी उन्हें बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन एक्ट्रेस में से एक माना जाता है.

सिद्धार्थ कोइराला

मनीषा कोइराला के भाई सिद्धार्थ कोइराला ने भी बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाई है. उन्होंने कुछ हिंदी फिल्मों में काम किया, जिनमें 'फन2श' और 'लकी: नो टाइम फॉर लव' जैसी फिल्में शामिल हैं.

माला सिन्हा

हिंदी सिनेमा के पुराने दौर की महान एक्ट्रेस माला सिन्हा का नेपाल से गहरा रिश्ता था. उनकी मां नेपाली थीं और उनका बचपन नेपाल में ही बीता. उन्होंने 'प्यासा', 'धूल का फूल', 'गुमराह' जैसी ढेरों क्लासिक फिल्मों में काम करके हिंदी फिल्मों के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया.

सुनील थापा

नेपाली सिनेमा के बड़े एक्टर सुनील थापा ने बॉलीवुड में विलेन के रोल में खूब नाम कमाया है. उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में काम किया है, जिनमें 'मेरी जंग', 'अंधा कानून' और 'वन टू का फोर' जैसी फिल्में शामिल हैं, जहां उनकी एक्टिंग को खूब पसंद किया गया.

झरना बज्राचार्य

मिस नेपाल 1997 रहीं झरना बज्राचार्य ने नेपाली फिल्म इंडस्ट्री के साथ बॉलीवुड में भी अपना जलवा बिखेरा है. उन्होंने कुछ हिंदी गानों के वीडियो और हिंदी फिल्मों में भी एक्टिंग की है. 'लव इन नेपाल' फिल्म से उन्होंने बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था.

माधुरी दीक्षित

ने 8 साल की उम्र में कर दिया था ये कमाल, अखबार में छप गई थी फोटो

माधुरी दीक्षित ने अपनी उम्दा अदाकारी से फैंस का खूब दिल जीता है. उन्होंने एक्टिंग के साथ-साथ डांस से भी अपनी खूब पहचान बनाई है. उन्होंने कई फिल्मों में अपना डांसिंग टैलेंट दिखाया है. उन्होंने बचपन में ही डांस सीखना शुरू कर दिया था और छोटी उम्र में ही इस वजह से एक बार अखबार में उनकी फोटो भी छपी थी.माधुरी दीक्षित ने 12वीं क्लास की परीक्षा देने के बाद गर्मियों की छुट्टियों में अपनी डेब्यू फिल्म की शूटिंग शुरू की थ. करीब 17 साल की उम्र में वो एक्ट्रेस बन गई थीं. एक्टिंग का हुनर तो माधुरी बॉलीवुड में आने के बाद सीखती चली गईं, लेकिन डांस में वो पहले से ही अव्वल थीं. एक बार तो उन्होंने ऐसा डांस किया था कि उनकी तस्वीर को अखबार में जगह मिली थी.

जब नन्हीं माधुरी ने लूट ली महफिल

3 साल की उम्र से शुरू कर दिया था कथक सीखना

माधुरी दीक्षित का जन्म 1 मई 1964 को स्नेहलता दीक्षित और शंकर दीक्षित के घर मुंबई में हुआ था. जिस उम्र में बच्चे ठीक से चलना भी नहीं जानते हैं उस उम्र में माधुरी ने डांस करना शुरू कर दिया था. बताया जाता है कि एक्ट्रेस ने सिर्फ 3 साल की उम्र से कथक की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी.

8 की उम्र में अखबार में छपी माधुरी की फोटो

माधुरी ने कथक की ट्रेनिंग लेने के बाद एक बार गुरु पूर्णिमा के मौके पर अपनी पहली परफॉर्मेंस दी थी. उस वक्त माधुरी की उम्र आठ साल थी. माधुरी ने इतना शानदार डांस किया था कि तब एक अखबार में तस्वीर के साथ उनकी खबर छपी थी और लिखा गया था, लिटिल गर्ल स्टोल द शो. यानी छोटी बच्ची ने शो चुरा लिया.

माधुरी की बेहरीन फिल्में

माधुरी ने अपना डेब्यू साल 1984 की फिल्म 'अबोध से किया था. माधुरी बॉलीवुड की सक्सेसफुल एक्ट्रेस में गिनी जाती हैं. उन्होंने 'दयावान', 'तेजाब', 'टोटल धमाल', 'बेटा', 'साजन', 'खलनायक', 'हम आपके हैं कौन' दिल और 'राजा' सहित कई बेहतरीन फिल्में दी हैं.

मोबाईल फोन पर नहीं घटी GST की दर, सरकार के फैसले से लोग निराश- अनिक टेलीकॉम के मालिक रमन

शिवानी कौर बमराह

दिव्य दिल्ली : देश में 2017 में लागू हुआ वस्तु एवं सेवा कर (GST) आठ साल बाद एक बड़े सुधार से गुजरा है। जीएसटी काउंसिल की बैठक में सरकार ने टैक्स ढांचे को सरल बनाने के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया। अब पूरे सिस्टम में केवल दो ही टैक्स स्लैब रहेंगे - 5% और 18%। सरकार का कहना है कि इस कदम से टैक्स प्रक्रिया आसान होगी और कारोबारियों पर जटिलता का बोझ कम होगा। इसी बदलाव को लेकर लोगों की राय जानने पहुँची दिव्या दिल्ली न्यूज की टीम। नांगलोई के शिव राम पार्क में स्थित अनिक टेलीकोम शोरूम के मालिक रमन से बात हुई। उन्होंने जीएसटी में हुए इस बदलाव को लेकर अपनी राय रखी। रमन ने बताया कि अब मोबाइल फोन पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। पहले यह दर 12% थी। इसका सीधा मतलब है कि मोबाइल फोन की कीमत अब उपभोक्ताओं के लिए बढ़ जाएंगी। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा

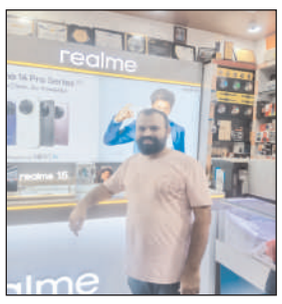

- "मान लीजिए कि किसी मोबाइल की कीमत 20,000 है। पहले 12% जीएसटी पर उपभोक्ता को 2,400 टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब 18% जीएसटी पर वही टैक्स 3,600 हो जाएगा।"उनका कहना था कि सरकार ने टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन जैसे अन्य इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों पर टैक्स घटाकर राहत दी है, लेकिन मोबाइल फोन पर दरें बढ़ाना आम उपभोक्ता के लिए बोझ साबित होगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा - "जैसे अन्य पदार्थों पर जीएसटी कम की गई है, वैसे ही मोबाइल फोन पर भी राहत मिलनी चाहिए थी।"तरविंदर सिंह ने आगे सुझाव देते हुए कहा कि भारत जैसे देश में मोबाइल फोन सिर्फ एक लग्जरी प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि यह पढ़ाई, कारोबार और रोजमर्रा के जीवन का अहम हिस्सा बन चुका है। ऐसे में टैक्स का बढ़ना डिजिटल इंडिया मिशन और उपभोक्ताओं दोनों के लिए कठिनाई पैदा करेगा। जीएसटी काउंसिल के इस फैसले ने एक ओर जहाँ टैक्स ढांचे को सरल बनाने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है, वहीं दूसरी ओर मोबाइल उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ डाल दिया है।

नेपाल में सैर करने गए झांसी के 4 युवक फंसे, प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से लगाई गुहार

झांसी। नेपाल हिंसक घटनाओं में झुलस रहा है। ऐसे में नेपाल सैर करने के लिए गए उत्तर प्रदेश के झांसी के चार युवक पोखरा में फंस गए हैं। इन युवकों ने इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी से मदद की गुहार लगाई है। उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

झांसी के नवाबाद थाना क्षेत्र स्थित शिवाजी नगर निवासी संदीप सोनी ने इंस्टाग्राम पर वीडियो जारी कर बताया कि वह झांसी से अपने तीन

मित्रों के साथ 8 सितंबर को फ्लाइट से निकला था और 9 सितंबर को दोपहर वे सभी पोखरा पहुंच गए थे। यहां पहुंचने के बाद पता चला कि यहां के हालात बेहद खराब हैं।

उन्होंने बताया कि जिस होटल में रुके थे वहां सायं करीब 7 बजे हमला हो गया। उनके अलावा होटल में करीब 50 लोग मौजूद थे। हमले के कुछ देर बाद सेना के जवान वहां पहुंच गए और बचाव अभियान चलाकर पहाड़ के एक होटल पर शिफ्ट किया। परिवार के लोगों से उन युवकों की बात हो रही है।

चार महीने की बच्ची में पाए गए ह्यूमन टेल को सफलतापूर्वक सर्जरी के माध्यम से हटाया

मो अजीज सैफी

दिव्य दिल्ली: दिल्ली एम्स के डॉक्टरों ने चार महीने की बच्ची में पाए गए ह्यूमन टेल को सफलतापूर्वक सर्जरी के माध्यम से हटाया है। सर्जरी करने वाले न्यूरो सर्जरी के एडिशनल प्रोफेसर डॉ. अमोल रहेजा ने बताया कि यह एक बेहद दुर्लभ स्थिति है, दुनिया में अभी तक केवल 66 ऐसे मामले दर्ज हुए हैं। बच्ची के कमर के पास लगभग 12 सेंटीमीटर लंबा उभार पाया गया था, जिसे जांचने पर ह्यूमन टेल के रूप में पहचाना गया। बच्ची छत्तीसगढ़ के एक छोटे गांव की रहने वाली थी और गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। स्थानीय डॉक्टर की सलाह पर परिवार एम्स पहुंचा। डॉ. अमोल ने बताया कि सर्जरी सफल रही है और बच्ची सामान्य जीवन जी सकती है। इस प्रकार

की सर्जरी जन्म के पांच-छह महीने बाद ही की जाती है और इसमें मांसपेशियों और नसों की जटिलताओं के कारण बहुत सावधानी की आवश्यकता होती है। सर्जरी में डॉ. अमोल के अलावा दो अन्य डॉक्टर और एनेस्थीसिया टीम ने अहम भूमिका निभाई।

भारतीय किसान यूनियन (अंबावता) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक आयोजित हुई

मो अजीज सफी

दिव्य दिल्ली : राजधानी दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भारतीय किसान यूनियन (अंबावता) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी रिशिपाल अंबावता ने की। बैठक के दौरान 5 नवंबर को तालकटोरा स्टेडियम में "किसान बचाओ -देश बचाओ" नाम से होने वाली विशाल रैली की घोषणा की गई। इस रैली में करीब 20 हजार किसान शामिल होंगे और सरकार बदलने का ऐलान भी किया जाएगा। रैली में किसानों के हित और कई अहम मुद्दों पर चर्चा कर आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। चौधरी रिशिपाल ने कहा कि देश में चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराए जाने चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि जब राष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से हो सकता है, तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव ईवीएम से क्यों? बैठक में पंजाब से हरजीत कौर, रिटायर्ड कैप्टन अनुभव यादव समेत कई संगठनों के नेता इडव अंबावता में शामिल हुए। कार्यक्रम का संचालन राष्ट्रीय प्रवक्ता अनीश गाजी एडवोकेट ने किया।

सोने-चांदी पर कम हो जीएसटी- निहाल विहार स्थित कृष्णा ज्वैलर्स ने दिया बयान

शिवानी कौर बमराह

दिव्य दिल्ली: भारत सरकार द्वारा GST की नई दरें घोषित की गई हैं इसी विषय पर दिल्ली के निहाल विहार में स्थित कृष्णा ज्वैलर्स के मालिक बलराम चौधरी ने सोने-चांदी पर लगने वाले GST को लेकर बड़ा बयान दिया है। फिलहाल सोने-चांदी पर 3 प्रतिशत GST लागू है, लेकिन बलराम चौधरी का कहना है कि अगर सरकार इस टैक्स को 3 से घटाकर कम कर दे, तो इसका सीधा फायदा ग्राहकों और ज्वैलर्स दोनों को मिलेगा। और साथ ही धर्मेंद्र चौधरी का कहना है कि मेकिंग चार्ज पर 5 प्रतिशत की दर को भी कम करना चाहिए क्योंकि

टैक्स दर कम होने से ग्राहकों को खरीदारी में राहत मिलेगी, वहीं ज्वैलर्स का कारोबार भी और बेहतर होगा। उन्होने सरकार से इस पर गंभीरता से विचार करने की अपील की है।

सोने-चांदी पर कम हो जीएसटी- शिव राम पार्क स्थित संदीप ज्वैलर्स ने सांझा किए अपने विचार

शिवानी कौर बमराह

दिव्य दिल्ली:भारत सरकार द्वारा GST की नई दरें घोषित की गई हैं इसी विषय पर दिल्ली के नांगलोई के शिव राम पार्क में स्थित संदीप ज्वैलर्स के मालिक संदीप वर्मा ने सोने-चांदी पर लगने वाले GST को लेकर बड़ा बयान दिया है। फिलहाल सोने-चांदी पर 3 प्रतिशत GST लागू है, लेकिन संदीप वर्मा का कहना है कि अगर सरकार इस टैक्स को 3 से घटाकर कम कर दे, तो इसका सीधा फायदा ग्राहकों और ज्वैलर्स दोनों को मिलेगा। उनका कहना है कि मेकिंग चार्ज पर 5 प्रतिशत की दर को भी कम करना चाहिए क्योंकि टैक्स

दर कम होने से ग्राहकों को खरीदारी में राहत मिलेगी, वहीं ज्वैलर्स का कारोबार भी और बेहतर होगा।

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय नजरबंद

लखनऊ

राजधानी लखनऊ में गुरुवार को पुलिस ने कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को उनके घर पर नजरबंद कर लिया। राय ने 11.30 बजे प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कान्फ्रेंस बुलाई थी। वह कान्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए घर से निकलते इससे पहले ही पुलिस ने दस्तक दी। इसके बाद उन्हें घर से नहीं निकलने दिया गया।

इस पर अजय राय ने एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने लिखा कि, 'पुलिस भेजकर हमें रोकना, कार्यकर्ताओं की आवाज दबाना। ये लड़ाई को रोक नहीं पाएगा, ये वोट चोरों को बचा नहीं पाएगा'।

उन्होंने आगे लिखा कि 'कांग्रेस का हर बब्बर शेर कार्यकर्ता गली-गली, गांव-गांव से विरोध करेगा। आवाज देगा। 'मोदी, वोट चोरी बंद करो!' दरअसल, पीएम मोदी के वाराणसी दौरे को लेकर अजय राय ने प्रदर्शन का एलान किया था। इसी को लेकर वह प्रेस वार्ता भी करने वाले थे। लेकिन, इससे पहले ही उन्हें नजरबंद कर लिया गया। घर से नहीं निकलने दिया गया।

चंदर विहार में पल्स अस्पताल में बेटी के जन्म पर नि:शुल्क उपचार किया जाता है

शिवानी कौर बमराह

दिल्ली के चंदर विहार में स्थित पल्स मल्टी-स्पेशलिस्ट अस्पताल में सभी बीमारियों के उपचार किए जाते हैं। अस अवसर पर पल्स अस्पताल के संचालक डॉक्टर पवन कुमार से खास मुलाकात हुई इस दौरान डॉक्टर पवन ने जानकारी दी कि पलस अस्पताल में बेटी के जन्म पर जच्चा-बच्चा का नि:शुल्क उपचार किया जाता है और अस्पताल में सभी बीमारियां का उपचार विशेषज्ञ की देखरेख में किया जाता है।

स्कूली बस की टक्कर से बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद में साढ़ क्षेत्रान्तर्गत गोपालपुर गांव के पास गुरुवार को एक स्कूली बस अनियंत्रित होकर एक मोटरसाइकिल को टक्कर मारते हुए नहर के माइनर में पलट गयी। घटना में बाइक सवार पिता-पुत्र की मौत हो गयी, जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई।

सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत

नोएडा। थाना सेक्टर 49 क्षेत्र के बरौला गांव के पास बीती रात को एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मार दिया। इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए नोएडा के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उपचार के दौरान उनको मृत घोषित कर दिया

थाना सेक्टर 49 के प्रभारी निरीक्षक अनुज कुमार सैनी ने बताया कि टीटू पुत्र राजकुमार उम्र 26 वर्ष हाल निवासी सेक्टर 79, मूल निवासी जनपद अलीगढ़ बीती रात को बाइक पर सवार होकर बरौला गांव के पास से गुजर रहे थे, तभी एक अज्ञात वाहन चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए उन्हें टक्कर मार दिया। उन्होंने बताया कि इस घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें उपचार के लिए नोएडा की जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि थाना सेक्टर 49 पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। उन्होंने बताया कि पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सुप्रीम पाइप के नाम से नकली सामान बेचने वाला गिरफ्तार

गौतमबुद्ध नगर। थाना बादलपुर पुलिस ने एक नामी कंपनी के नाम से प्लास्टिक की नकली पाइप बेचने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसके खिलाफ कंपनी के एक अधिकारी ने मुकदमा दर्ज करवाया है।

13 और 8 साल के किशोरों ने छह वर्षीय मासूम के साथ की दरिंदगी, दोनों पुलिस हिरासत में

कानपुर। उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित जाजमऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत महज 13 और आठ साल के दो किशोरों ने पांच रुपये का लालच देकर छह साल की एक मासूम बच्ची को अपनी हवस का शिकार बना लिया। काफी जद्दोजहद के बाद बच्ची दरिंदो के चंगुल से छूटकर रोते-बिलखते अपने घर पहुंची। सूचना पर पहुंची पुलिस मासूम का मेडिकल कराते हुए दोनों लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

समाज मे फैली विकृत मानसिकता ने छोटे-छोटे बच्चों को भी अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है, जिसके चलते नाबालिक बच्चे भी ऐसे कृत्य करने लगे है कि जिसके बारे में कल्पना भी नही की जा सकती है। घटना थाना जाजमऊ क्षेत्र के छबीलेपुरवा की है। यहां रहने वाले 13 वर्षीय और आठ वर्षीय दो किशोरों की नीयत पड़ोस में रहने वाली छह साल की मासूम बच्ची पर बिगड़ गई। उन्होंने बच्ची को अकेला पाकर उसे पांच रुपये का लालच दिया और बहला-फुसलाकर अपने साथ पास के ही एक सूने और बंद पड़े मकान में ले गए।उस सुनसान घर में दोनों ने मिलकर बच्ची के साथ हैवानियत की हदें पार कर दीं। जब दर्द से कराहती बच्ची ने चिल्लाने की कोशिश की, तो आरोपियों ने

उसका मुंह दबा दिया। ताकि उसकी आवाज बाहर न जा सके और कोई उनकी करतूत जान न पाए।

किसी तरह दरिंदों के चंगुल से छूटकर मासूम बच्ची रोते-बिलखते अपने घर पहुंची। उसकी हालत देखकर माँ घबरा गई। जब माँ ने उससे प्यार से पूछा तो बच्ची ने अपने साथ हुई दरिंदगी की पूरी कहानी बताई, जिसे सुनकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में कोहराम मच गया और उन्होंने बिना देर किए तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपी नाबालिग किशोरों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है।

घटना की सूचना पर एसीपी कैंट आकांक्षा पाण्डेय भी मौके पर पहुंचीं और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ित बच्ची के परिजनों से बात की। एसीपी के निर्देश पर बुधवार की देर रात पीड़ित बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया गया।

एसीपी कैंट आकांक्षा पाण्डेय ने बताया कि 13 वर्षीय किशोर द्वारा छह वर्षीय किशोरी से रेप करने की बात सामने आई है। इस घिनौने कृत्य में उसका आठ वर्षीय दोस्त भी सहयोगी था। दोनों नाबालिगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बच्ची का मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है और रिपोर्ट के आधार पर कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वाराणसी में भारत-मॉरीशस द्विपक्षीय वार्ता शुरू

नरेन्द्र मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री का गर्मजोशी से किशा स्वागत

वाराणसी। उत्तर प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में गुरुवार को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भारत और मॉरीशस के बीच द्विपक्षीय वार्ता शुरू हो गई है। वार्ता की शुरूआत से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. रामगुलाम का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता शुरू हुई।

नदेसर स्थित तारांकित होटल ताज में आयोजित इस उच्चस्तरीय बैठक शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मॉरीशस के प्रधानमंत्री डॉ. नवीनचंद्र रामगुलाम का गर्मजोशी से स्वागत किया। दोनों नेताओं के बीच सकारात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता हुई।

इस वार्ता में आर्थिक सहयोग, पर्यटन, और रणनीतिक साझेदारी सहित अनेक अहम मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई।

बैठक के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की। खासतौर पर विकासात्मक साझेदारी, क्षमता निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, बुनियादी ढांचा, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और नीली अर्थव्यवस्था जैसे उभरते क्षेत्रों में सहयोग को विस्तार देने पर विमर्श हुआ।

दरअसल, हिंद महासागर क्षेत्र में मॉरीशस भारत का एक प्रमुख समुद्री पड़ोसी और रणनीतिक भागीदार है। भारत के ह्यसागरह्ल (क्षेत्रों में सुरक्षा एवं विकास के लिए पारस्परिक और समग्र सहयोग) दृष्टिकोण और ह्यपड़ोसी पहलेह्ल नीति में मॉरीशस की भूमिका बेहद अहम है। विशेषज्ञों का मानना है कि दोनों देशों के बीच बढ़ता सहयोग न केवल आपसी विकास के लिए बल्कि ग्लोबल साउथ की साझा आकांक्षाओं को भी मजबूती प्रदान करेगा।

इससे पहले मार्च 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की मॉरीशस यात्रा के बाद यह दौरा द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

काशी का यह शिखर सम्मेलन पारस्परिक समृद्धि, सतत विकास और सुरक्षित एवं समावेशी भविष्य की दिशा में भारत और मॉरीशस की साझा यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि साबित होगा।

दुग्ध उत्पादों पर जीएसटी कम करने पर धन्यवाद मोदी जी वाली होर्डिंग - राष्ट्रीय यदुवंश परिषद

वाराणसी। राष्ट्रीय यदुवंश परिषद ने दुग्ध उत्पादों पर जीएसटी कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी सहित प्रदेश के कई जनपदों में होर्डिंग लगाकर धन्यवाद ज्ञापित किया है।

राष्ट्रीय यदुवंश परिषद के संरक्षक एवं भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जीएसटी काउंसिल द्वारा दुग्ध उत्पादों पर जीएसटी में भारी राहत

देने का जो निर्णय लिया गया है, वह पशुपालक समाज, दुग्ध विक्रेता समाज और विशेष रूप से यादव समाज के लिए एक बड़ी सौगात है।

प्रदेश महामंत्री सुभाष यदुवंश ने कहा कि यह केवल एक आर्थिक निर्णय नहीं, बल्कि हमारे परिश्रमी दूध उत्पादकों के सम्मान का प्रतीक है। इस फैसले ने दूध उत्पादन से जुड़े लाखों परिवारों को राहत दी है और आत्मनिर्भरता की ओर एक मजबूत कदम बढ़ाया है। इस फैसले पर ही "धन्यवाद मोदी जी" की होर्डिंग्स लगाकर ऐतिहासिक निर्णय के लिए प्रधानमंत्री को आभार प्रकट किया गया है। वाराणसी सहित प्रदेश का यादव समाज पूरी तरह से गदगद है।

Published, printed and owned by Rajesh.Chauhan, printed at Dinesh Sharma 19, DSIDC Sheds, Scheme 3, Okhla Phase-2 New Delhi -110020 and published at BG 6 305 B Paschim Vihar New Delhi --110063 Editor Rajesh.Chauhan. E mail ID-rajeshchauhan4569@gmail.com, Contact No. - 9873104569, RNI No.- DLHIN/25/A2321